A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 12 जुलाई, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 303, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

कल जन्मूंगा मैं
मैं अब तक नहीं
हुआ पैदा

यह मुझसे पहले का
समय है जो
इसी तरह जाना जायेगा

हैं जगहें कितनी सारी
जहां नहीं मैं
कितने सारे हैं लोग
नहीं जिन्हें पता
कि हूं मैं

कल कोई सूचना देगा
देगा बाज बधाई
तब पता चलेगा

अभी इतने विशाल समय में
और ब्रह्मांड में विराट
बिंदु सा ओझल नन्हा
कहां दिख रहा

ठीक पूर्व जन्म से अपने
अपने से अधिक किसे पता
अपने न होने की
अपने कल हो सकने की
बात लिख रहा।

–सुधीर मोता

प्रसंगवश

जाति गणना नहीं, वोट की संख्या गिन रही हैं पार्टियाँ?

– अरविंद मोहन

राजनीतिक दल क्या जाति आधारित गणना के नाम पर सीधे वोटों की गणना और समीकरण पर ध्यान दे रहे हैं? क्या इससे जातीय राजनीति का स्वरूप बदल रहा है या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है?

बिहार चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में सुधार या नए नाम जोड़ने की कवायद के नाम पर जो कुछ चल रहा है, वह देश कई राजनीति और सुप्रीम कोर्ट के कार्य-व्यापार के प्रमुख मुद्दों में है। बिहार में तो इससे गहमा गहमी है ही। वहाँ विपक्ष इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा है तो सत्ता पक्ष के कई दल भी इन क़दमों का खुला समर्थन नहीं कर रहे हैं। जगह-जगह वोटर फार्म न भरने की मुहिम चल रही है तो कई जगहों से फार्म लेकर आए बूथ लेवल अधिकारी को खदेड़े जाने की ख़बर भी आई है। कई लोग इसे असम जैसी स्थिति की शुरुआत मानते हैं तो कई पश्चिम बंगाल चुनाव का रिहर्सल।

लेकिन सुदूर दक्षिण में भी इसी तरह का एक हंगामा चल रहा है। वहां अनुसूचित जातियों के लोगों की जातिवार जनगणना का काम चल रहा है। वहाँ भी विपक्षी भाजपा हंगामा मचा रही है तो कैबिनेट के दो दलित मंत्री मुनियप्पा और महादेवप्पा मुख्यमंत्री पर दबाव बना रहे हैं और गिनती के तरीक़े पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। आपत्ति का मुद्दा 101 दलित जातियों को अलग-अलग गिनना है जिसे दलित अपने समाज में विभाजन की राजनीति से जोड़ रहे हैं तो सरकार सही संख्या जानकार संसाधनों के उचित बँटवारे का तर्क दे रही है। वहां भी क्यूआर कोड के ज़रिए अप्रकट ढंग से जाति दर्ज कराने का विकल्प भी दिया जा रहा है। पर पर्याप्त चेतन दलित समूहों, खासकर शहरों में रहने वाले, को इस तरह की गिनती पर आपत्ति है।

सबको मालूम है कि कर्नाटक में जातिवार गणना हो चुकी है, लेकिन उससे सामने आई संख्या और प्रतिशत को लेकर कांग्रेस के अंदर ही बवाल है। सिद्धारमैया और राजशेखर लगातार आमने-सामने रहे हैं। जो फ़ैसला हुआ है उससे जातिवार गनगणना कराने का राजनैतिक हंगामा थम गया है। अब श्रेय लेने की राजनीति ऊपर आ गई है। सबसे ज्यादा बड़ा दावा तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ही है। उनके समर्थक तो जातिवार जनगणना कराने वाली बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री रहे तेजस्वी के दावे को भी पीछे कर रहे हैं। बीजेपी ने तब भी सहमति दी थी और अब उसका ही फ़ैसला है। सो वह दावेदार है। वह सुविधा से यह भुला दे रही है कि बिहार सरकार द्वारा जातिवार गिनती के बाद लाई नई आरक्षण नीति के ख़िलाफ़ उनकी सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई थी और अब भी वह मुक़दमा चल रहा है।

इस हंगामे में किसी को यह होश नहीं है कि बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना के फ़ैसलों की ही नहीं पिछली जनगणना में जुटाए जातिवार गिनती के आँकड़े जाहिर न करने जैसे फ़ैसलों के पीछे क्या अच्छाई या बुराई रही है और क्यों पार्टियां इसके पक्ष में भी दिखाना चाहती हैं और विरोध भी करती हैं, मामले को टालना भी चाहती हैं। क्यों जातियों के अंदर से भी खुद को इस तरह गिनवाने के खिलाफ़ आवाज़ें आने लगी हैं जैसा कर्नाटक में खुलकर दिखता है। यह सिर्फ़ कर्नाटक की बात नहीं है।

हर जगह का दलित समाज खुद के अंदर बंटवारा और श्रेणीकरण के खिलाफ़ है। और अब ओबीसी जातियों के अंदर से भी अलग-अलग जातियों की गिनती के खिलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं। हम जानते हैं कि बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों ने दलितों की दो श्रेणियां बनाई हैं तो अधिकांश राज्यों ने अनुसूचित जाति और ओबीसी जातियों की सूची में जोड़ घटाव किए ही है। ऐसा इन समूहों के राजनैतिक दबाव से हुआ है तो अक्सर शासक जमात की अपनी राजनीतिक गिनती भी प्रभावी रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने ओबीसी जातियों की दो श्रेणियाँ बनाने के साथ लगातार दलित और महादलित का बँटवारा किया है और लगातार जातियों को इधर से उधर भी करते रहे हैं।

जो काम वे कर रहे हैं उसमे उनका अपना सामाजिक-राजनैतिक समर्थन का खयाल रहता है, लेकिन यही काम कांग्रेसी भी करते रहे हैं, बीजेपी तो आरक्षण की घोषित विरोधी ही रही है। नीतीश को अहीरों से राज लेना था, पासवानों को हाशिए पर रखना था, पचपनिया जातियों को साथ रखना था जो अगड़ों के साथ अहीर राज से भी त्रस्त थीं। इसलिए यह बंटवारा उनको बहुत लाभ दे गया और बिना संगठन और नीति के वे लगातार बीस साल राज पूरा करने जा रहे हैं। आज अति पिछड़ों के पीछे हर दल भाग रहा है क्योंकि उनकी आबादी 37 फ़ीसदी है। पर इसी से छोटी छोटी संख्या वाले डर भी रहे हैं।

बिहार में एक लाख से कम आबादी वाली सौ से ज़्यादा जातियाँ हैं। इन समूहों में डर व्याप्त है कि अगर उनको अकेले अकेले कर दिया गया तो उनकी पूछ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन राजनैतिक चेतना जगने के बाद उनको यह भी समझ आ रहा है कि पिछड़ा नाम से सारा लाभ अहीर न लें तो अति पिछड़ा कोटे से कलवार, तेली, सूढी ही क्यों सांसद-विधायक बनें या उनके ही बच्चे सरकारी नौकरियों में जाएँ। क्यों दलित नाम की मलाई संख्या में बहुत कम धोबी खा लें और हलखोर-बंसफोड़ और डोम जैसी जातियों को कुछ भी न मिले।

असल में हमारे समाज में जितने किस्म की वंचनाएं हैं और जितने किस्म के भेद भाव हैं, जाति आधारित आरक्षण उनमें से सिर्फ एक का निदान करता है और वह भी आधा अधूरा। इससे आने वाली राजनैतिक सामाजिक चेतना ज़रूर बाक़ी विसंगतियों को भी उजागर करती है लेकिन यह सारी वंचनाओं का जवाब नहीं है।

हमारे यहाँ जन्मजात भेदभाव सिर्फ़ जाति के आधार पर नहीं होता, यह लिंग, शिक्षा, क्षेत्र, गाँव-शहर, हिन्दी अंग्रेज़ी और आर्थिक कारणों से भी होता है। मौजूदा आरक्षण बहुत कम समय में इन सबका एहसास करा देता है। दलित आदिवासी आरक्षण ने ही ओबीसी आरक्षण का आधार बनाया। इससे गाँव-शहर, हिन्दी अंग्रेज़ी या लड़का-लड़की के भेद को समझना भी आसान हुआ है, अमीर गरीब का अंतर समझना भी। लेकिन सरकारों की इच्छा अभी वोट से ज़्यादा आगे नहीं गई है। वह समता लाने में दिलचस्पी नहीं रखती। वह तो नीतियों से क्या कर रही है यह अलग है अब समाजवाद शब्द पर भी आपत्ति होने लगी है। आरक्षण का तर्क इतना मज़बूत नहीं हुआ है कि बड़ा बदलाव करे। उसके लिए आरक्षण को अपने अंदर भी बदलाव करने होंगे।

(सत्य हिंदी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शॉल ओढ़ाने पर समझें अब उम्र हो गई: भागवत

कहा-75 साल का मतलब 'रिटायर' हो जाना चाहिए

नागपुर (एजेंसी)। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। भागवत ने ये बातें 9 जुलाई को रामजन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहीं। हालांकि, भागवत ने अपने बयान में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष इसे प्रधानमंत्री से जोड़ रहा है। मोदी और भागवत इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा- पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया था। अब देखते हैं क्या मोदी इसका खुद पालन करेंगे या नहीं। बीजेपी में राज्य और मंडलस्तर पर उम्र की सीमाएं लागू हैं भाजपा के भीतर एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं है। हालांकि, कुछ स्तरों पर उम्र सीमाएं लागू की गई हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ भाजपा ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए 35 से 45 साल और जिला अध्यक्ष पद के लिए 45 से 60 साल की उम्र सीमा निर्धारित की है। वहीं भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 75 साल से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया था। इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र, जैसे कई नेता शामिल थे। भाजपा ने 75 साल की उम्र पर कई नेता रिटायर किए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू।

- कांग्रेस बोली-पीएम मोदी भी इस साल 75 के होंगे

पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया।

महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश

राहुल बोले-इलेक्शन कमीशन भाजपा का काम कर रहा

भुवनेश्वर (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ओडिशा में कहा- महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। वह भाजपा के हिस्से का काम कर रहा है। अपना काम नहीं कर रहा है। राहुल ने आगे कहा- महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक पता नहीं चल पाया कि ये वोटर्स कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से कई बार कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट, वीडियोग्राफी दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। हम इलेक्शन कमीशन और भाजपा को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली 'संविधान बचाओ समावेश' सभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद रहे। अडाणी ओडिशा सरकार चलाते हैं। अडाणी नरेंद्र मोदी को चलाते हैं। जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, तो लाखों लोग इसे देखते हैं। फिर एक नाटक होता है।

- कांग्रेस नेता ने कहा- अडाणी चला रहे हैं ओडिशा सरकार

मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में मिले 30 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव : मुख्यमंत्री

प्रदेश के सभी शहरों में आयोजित करेंगे ग्रोथ कॉन्क्लेव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रियल एस्टेट आज देश का सबसे अधिक प्रोगेसिव सेक्टर है और यह सेक्टर देश के नवनिर्माण में बड़ा सहयोग दे रहा है। रियल एस्टेट के विकास में ही देश का विकास अंतर्निहित है। हम इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इसी तरह की ग्रोथ कॉन्क्लेव करके और सबको घर मुहैया कराकर नागरिकों के जीवन में खुशहाली लायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर देश की जीडीपी में अब 8.5 प्रतिशत तक योगदान दे रहा है, जो कभी मात्र 3 प्रतिशत हुआ करता था। उन्होंने गुजरात की 'गिफ्ट सिटी' का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी ही 10 स्मार्ट सिटीज़ मध्यप्रदेश में विकसित की जाएंगी। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश में 10 लाख नए आवास तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सेक्टरों के लिए विशेष ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति और नई दिशा मिलेगी।

प्रदेश के समग्र शहरी विकास और रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को इंदौर स्थित ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में 'मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025' को संबोधित कर रहे थे। इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश में 15 हजार से अधिक रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे और शहरी एवं औद्योगिक विकास को नई ऊचाईयां प्राप्त होंगी। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विकास के लिये 12 हजार 360 करोड़ रुपये की सौगातें भी दी।

प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के दिशा में ठोस प्रयास किये जा रहे हैं: विजयवर्गीय

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में आगामी 25 वर्षों की जरूरतों और इन्फास्टक्चर को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मिक्स्ड लैंड यूज और ईटीसी मॉडल को अपनाते हुए प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के दिशा में ठोस प्रयास किये जा रहे है। इंदौर शहर में देश में अपने कामों की वजह से विशिष्ट पहचान बनाई है।

कॉन्क्लेव में प्राप्त निवेश प्रस्ताव

कॉन्क्लेव में सर्वाधिक 12 हजार 473 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसी तरह होटल क्षेत्र में 3 हजार 344 करोड़ रूपये, रियल एस्टेट क्षेत्र में 1812.14 करोड़ रुपये, एजुकेशन क्षेत्र में 72.45 करोड़ रूपये, रिन्यूअल एनर्जी क्षेत्र में 500 करोड़ रूपये तथा आईटी क्षेत्र में 100 करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 12 निवेशकों से 2 हजार 784 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिये एक हजार 320 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है।

मुख्यमंत्री आज लाड़ली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे 26वीं किश्त

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार 12 जुलाई को ग्राम पंचायत नलवा जिला उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गैस सिलेंडर उज्जवला योजना के हितग्राहियों के खातों में जुलाई माह की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन के कालिदास अकादमी में राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन में मछुआ कल्याण के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं हितलाभ का वितरण भी करेंगे।मुख्यमंत्री डॉ. यादव लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत एक करोड़ 27 लाख बहनों को 1503 करोड़ 14 लाख की 26वीं किश्त उनके खातों अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 56 लाख 74 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ की राशि, 30 लाख से अधिक बहनों को उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफलिंग की 46 करोड़ 34 लाख की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरण करेंगे।

राम सिंह, यशपाल और रविंद्र भी ले रहे हैं विधवा पेंशन

- यूपी में सरकारी योजनाओं में बड़ा खेल,हुआ घोटाले का पर्दाफाश

लखनऊ (एजेंसी)। इससे पहले हम कहानी को आगे बढ़ाएं..पहले ये कुछ नाम पढ़ लीजिए। यशपाल, दीपू, रविंद्र सिंह और राम सिंह। आप कहेंगे कि इन नामों के आखिर क्या खास है। दरअसल ये पुरुष वो हैं, जो महिलाओं को मिलने वाली विधवा पेंशन उठा रहे हैं। जी हां, यूपी के बरेली में सरकारी योजनाओं में बड़ा खेल सामने आया है। बात सिर्फ विधवा पेंशन तक ही नहीं रुकी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धा पेंशन जैसी सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी सेंधमारी कर दी गई। इस गड़बड़झाले को अंजाम दिया बरेली के जिला सहकारी बैंक के दो बैंक मैनेजर ने। दोनों ने मिलकर करीब 1.31 करोड़ रुपये का खेल कर डाला। न प्रशासन को भनक लगी न उन लोगों को जिनके नाम से फर्जी खाते खोल दिए गए। योजनाओं का पैसा धड़ल्ले से इनकी जेब में आता चला गया। अब जब मामला खुला तो इन दोनों मैनेजर समेत 4 बैंक कर्मियों को सस्पेंड कर केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दरअसल एक किसान की जागरुकता की वजह से इस पूरे घोटाले की पोल खुल गई। शाहजहांपुर जिले के किसान को पता चला कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का पैसा उनके खाते में आया ही नहीं। पता करने की कोशिश तो जानकारी मिली कि फरीदपुर की ब्रांच के खाते में यह पैसा गया है। किसान ने बैंक को शिकायत की, मई में जब फरीदपुर ब्रांच में अचानक चेकिंग की गई तो पाया कि सिर्फ एक किसान को ही चूना नहीं लगाया जा रहा है बल्कि लाखों की रकम इधर से उधर की जा रही है। इन बैंक अधिकारियों ने 1-2 नहीं 400 फर्जी बैंक खाते खोल डाले और 1 करोड़ से ज्यादा का गबन कर डाला। इन्होंने पहले फर्जी बैंक खाते खुलवाए और फिर उन्हें लाभार्थियों के आधार कार्ड से लिंक कर दिया। चालाकी इतनी कि एक ही बैंक खाते से कई आधार कार्ड लिंक कर दिए और योजनाओं का पैसा जब भी भेजा जाता, तो वो सीधे फर्जी खाते में आ जाता। यूपी में सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े की खबरें पहले भी आती रही हैं। विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन का लाभ उन लोगों के खाते में भी जा रहा था, जो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। इसी के चलते प्रशासन की ओर से पेंशन योजनाओं में सत्यापन भी कराया जा रहा है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 12 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

40 खातों में 106 करोड़ 'जाति' के हिसाब से था रेट

● धर्मांतरण मामले में फूट रहा है छांगुर बाबा का तिलिस्म

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड और प्रवर्तन निदेशालय ने धर्मांतरण गिरोह के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर शिकंजा कस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी की जांच में सामने आया कि बाबा और उसके साथियों के पास 40 से अधिक बैंक खातों में 106 करोड़ रुपये से अधिक की रकम थी, जिनमें से अधिकांश पैसा पश्चिम एशिया से आया हुआ बताया गया है। छांगुर बाबा का असली नाम जमालुद्दीन है। यूपी के बलरामपुर के रेहरा

माफी गांव का निवासी है। कभी छोटे स्तर पर रत्न बेचने वाला यह शख्स मुंबई के हाजी अली दरगाह जाता था और वहीं से उसका आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। धीरे-धीरे वह खुद को रूहानी बाबा बताने लगा। 2020 के बाद छांगुर बाबा की आर्थिक स्थिति अचानक बदल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कथित रूप से अपने चमत्कारी इलाज और दुआओं से हजारों लोगों को अपने प्रभाव में लिया और धीरे-धीरे 3,000 से 4,000 गैर-मुस्लिमों का धर्मांतरण कराया, जिनमें से 1,500 से ज्यादा महिलाएं थीं। धार्मिक प्रवचन, इलाज, और आश्चर्यजनक चमत्कारों के नाम पर लोगों को आकर्षित किया जाता था। फिर धीरे-धीरे उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जाता था।

शहीद पायलट ऋषिराज सिंह का अंतिम संस्कार

● फफक-फफक कर रोने लगे पिता छोटे भाई ने दी मुखाग्नि

पाली (एजेंसी)। चूरू में जगुआर फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा (23) का पैतृक गांव में सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई युवराज सिंह ने उनको मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान पिता जसवंत सिंह भावुक हो गए और रोने

लगे। वायुसेना के जवानों ने शहीद ऋषिराज सिंह को गार्ड ऑफ ऑन देकर आखिरी सलामी दी। इससे पहले पैतृक गांव में शहीद की तिरंगा यात्रा निकाली गई। आगे वायुसेना के जवान पीछे गांव वाले भारत की माता की जय और ऋषिराज अमर रहे के नारे लगाते हुए चले। शहीद की पार्थिव देह शाम करीब 6.10 बजे पैतृक गांव खिवांदी (पाली) लाई गई। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए घर के आंगन में पार्थिव देह को रखा गया, जहां परिजनों और आसपास के गांवों से आए लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट से हरियाणा सरकार का किनारा

● वन मंत्री बोले-केंद्र सरकार की मदद के बिना है मुश्किल

चंडीगढ़ (एजेंसी)। साढ़े 9 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हरियाणा की नायब सरकार बैकफुट पर दिख रही है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट अरावली की पहाड़ियों में 10 हजार एकड़ में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री खट्टर लगातार

सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम नायब सैनी और वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर के साथ गुजरात के वनतारा का दौरा किया। इससे पहले साल 2022 में मुख्यमंत्री रहते वह शारजाह (दुबई) सफाई के दौरे पर गए थे। तब उनके साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे। गुजरात के वनतारा दौरे के बाद हरियाणा सरकार अब इस प्रोजेक्ट को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह जंगल सफारी बनाने और फिर उसके संचालन के लिए हर महीने खर्च होने वाला मोटा फंड है।

हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालय

सावन के पहले दिन मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। शुक्रवार को सावन का पहला दिन रहा। इसके चलते देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं,

● फूलों से सजे मंदिर,वाराणसी से उज्जैन तक भारी भीड़

उज्जैन बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा समाप्त होने के साथ ही 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो गई। ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग भोर से ही मंदिरों में लंबी लाइन लगाए हुए दिखे। इसके साथ ही मंदिरों को फूलों से सजाया गया। लोग पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दिल्ली, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, अयोध्या के साथ-साथ तमाम शहरों में लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस बार सावन का महीना 29 दिन का होगा और ये 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे- पहला 14 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा 4 अगस्त। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, सावन महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था।

ऐसे में सावन की शुरुआत से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो पूरे महीने जारी रहने वाली है। सावन के चारों सोमवार को श्रद्धा और नियम के साथ पूजा करने पर भगवान शिव सभी कठिनाइयों को हर लेते हैं, ऐसी सोच के साथ श्रद्धालु भोले बाबा पर जल चढ़ाने पहुंचते हैं। हर सोमवार भगवान शिव को विशेष रूप से अलग-अलग वस्तुओं का अर्पण करने से जीवन के दोष, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। इसी श्रद्धा के साथ भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं।

सिंधु पर भारत के 'प्लान' से दहशत में पाकिस्तान

चिनाब नदी पर क्वार बांध परियोजना को गति देने की है तैयारी

इस्लामाबाद (एजेंसी)। सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच भारत ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर एक

● बुरी तरह फंसी शहबाज सरकार बढ़ जाएगी पाकिस्तान की टेंशन

महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना क्वार बांध के निर्माण में तेजी लाने जा रही है। इसके लिए 3119 करोड़ रुपये के कर्ज की मांग की गई है। एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है। भारत ने ये कदम सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले के बाद उठाया है, जिससे पाकिस्तान में नदी के निचले इलाके में पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत सरकार ने 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इस संधि के तहत भारतीय क्षेत्र से होकर बहने वाली छह नदियों में से तीन का पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में आतंकवाद को फैलाना बंद नहीं करता, संधि स्थगित रहेगी। पहलगाम आतंकी हमलेकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। हमले के कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाकिस्तान में दिए गए एक संबोधन में कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। मुनीर ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंदू और मुसलमान को दो अलग कौम हैं, जो एक साथ शांति से नहीं रह सकते। माना जाता है कि मुनीर के भाषण ने ही कश्मीर में पर्यटकों पर हुए बर्बर हमले की भूमिका लिखी थी।

● इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मामले में खुलासा

बेटी के एकेडमी चलाने से था नाराज, इसलिए की हत्या

गुरुग्राम (एजेंसी)। हरियाणा के गुरुग्राम में जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार की है। पुलिस ने आरोपी दीपक यादव को घर से ही अरेस्ट किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थीं, उससे अच्छी कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। इससे वह नाराज था। परिजन के मुताबिक 25 साल की राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही सवा करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन महीनेभर बाद ही एकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। परिवार से यह भी पता चला कि एकेडमी को लेकर 15 दिन से बाप-बेटी में रोजाना झगड़ा हो रहा था। गुरुवार को भी पिता ने उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका नहीं मानी और दोनों में बहस हुई। जिसके बाद आरोपी पिता ने गुस्से में आकर उसे गोलियां मार दीं। हालांकि, पहले सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर हत्या करने की बात सामने आई थी।

किचन में खाना बनाते वक्त 3 गोलियां मारीं

आरोपी दीपक के भाई कुलदीप यादव ने पुलिस को दी शिकायत की है। कुलदीप ने कहा कि सेक्टर 57 के सुशांत लोक फेस-2 में स्थित घर की पहली मंजिल पर दीपक, उसकी पत्नी मंजू और बेटी राधिका रहते थे, जबकि मैं अपने परिवार के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूं। गुरुवार सुबह दीपक का राधिका के साथ एकेडमी बंद करने को लेकर विवाद हुआ। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, उसी वक्त दीपक ने पीछे से उसे अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 गोलियां मार दीं। कुलदीप ने कहा कि सुबह के समय मैं ग्राउंड फ्लोर पर था। मैंने तेज आवाज सुनी और जब मैं पहली मंजिल पर गया तो राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़े पाया। जबकि पिस्टल ड्राइंग रूम में पड़ी थी।

एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए

ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले एनएसए अजीत डोभाल

चेन्नई (एजेंसी)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए। भारत को नुकसान की खबरें चलाईं। उन्होंने कहा

● राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले- हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए

कि विदेश मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया। ना यह बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। डोभाल ने यह बात शुक्रवार को आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में कही।

एनएसए ने कहा- वे कहते रहे कि पाकिस्तान ने ये किया, वो किया लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो। हमसे कोई चूक नहीं हुई। हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने 26 टूरिस्ट्स की हत्या कर दी थी।

इसके जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी। इस दौरान सेना ने 100 आतंकी मार

गिराए थे। दोनों देशों के बीच 10 मई की शाम 5 बजे से सीजफायर पर सहमति बनी थी। डोभाल ने कहा, टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के बीच संबंध हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। हमें गर्व है कि इस दौरान हमने स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल की। हमने सीमापार नौ पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले का फैसला किया था। इनमें एक भी ठिकाना बॉर्डर के पास नहीं था। हमारे सभी निशाने सटीक थे। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उन्होंने कहा, आप एक ऐसे देश, एक ऐसी सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं, जो हजार सालों से संकटग्रस्त और लहूलुहान रही है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं पता कि राष्ट्र की इस धारणा को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कितना अपमान और तकलीफ सही होगी। राष्ट्र, राज्य से अलग होता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में हजारों सालों से अस्तित्व में है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमले किए थे। इसमें एयरबेस के रनवे, हैंगर और इमारतों को नुकसान पहुंचा था। इनमें सरगोधा, नूर खान (चकलाला), भोलारी, जैकोबाबाद, सुक्कुर और रहीम यार खान एयरबेस शामिल हैं। एयरबेस पर हुए नुकसान की हाई क्वालिटी सैटेलाइट तस्वीरें 14 मई को सामने आई थीं। एयर मार्शल एके भारती ने 12 मई को बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर चुनिंदा मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया था।

● बीजेपी ने गैर मराठा वोटों को साधने की शुरू की कोशिश

मराठा-पेशवा पॉलिटिक्स से महाराष्ट्र में 'खेला' की तैयारी

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में मराठा पॉलिटिक्स के साथ पेशवा पर राजनीति शुरू हो गई है। खासकर 4 जुलाई के बाद से, जब गृह मंत्री अमित शाह ने खडकवासला स्थित

● अपने पक्ष में एकजुट करने में जुटी पार्टी, विपक्ष भी तैयार

नेशनल डिफेंस अकैडमी में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके पहले बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने पुणे स्टेशन का नाम बदलकर पेशवा बाजीराव प्रथम के

नाम पर रखने की मांग की थी। यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने गैर मराठा वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए बाजीराव पेशवा को पहचान दी जा रही है। अमित शाह के कार्यक्रम के बाद पेशवा के विरासत पर भी बहस छिड़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र में 32 प्रतिशत मराठे हैं, जो करीब 150 विधानसभा सीटों पर प्रभावशाली हैं। राज्य में बने 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठे हैं। इसके अलावा राज्य की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं ने भी बड़ा कद हासिल किया है। वहां दशकों से मराठा और ब्राह्मणों के बीच राजनीतिक वर्चस्व मुद्दा रहा है। राजनीतिक तौर पर नायकों के चुनाव में इसका असर रहा। शिवाजी महाराज हिंदुत्व के प्रतीक बन गए।

ओडिशा में 40 हजार से ज्यादा महिलाएं हो गई हैं गायब:राहुल

भुवनेश्वर में गरजे कांग्रेस नेता,बीजेपी सरकार पर किया बड़ा प्रहार

भुवनेश्वर (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को भुवनेश्वर के बारामुंडा मैदान में एक विशाल रैली 'संविधान बचाओ समावेश' को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां पर गईं। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां पर अत्याचार होता है। यहां की सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, 'ओडिशा सरकार का एक ही काम है कि राज्य के गरीब लोगों के हाथों से ओडिशा का धन चुराना। पहले बीजेडी सरकार ने यही किया और अब बीजेपी सरकार यही कर रही है। एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, किसान और मजदूर हैं, और दूसरी तरफ 5-6 अरबपति और बीजेपी सरकार है। यह लड़ाई जारी है। केवल कांग्रेस कार्यकर्ता, ओडिशा की जनता के साथ मिलकर, इस लड़ाई को जीत सकते हैं, कोई और नहीं।' कांग्रेस सांसद ने कहा, 'बीजेपी लगातार संविधान पर आक्रमण कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, उसी तरह से बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव चोरी करने के लिए चुनाव आयोग ने नई साजिश शुरू की है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर में एक बगिया मां के नाम अभियान में उपस्थित ऋषिश्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर में एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया।

विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

पति बोला-दूसरे से बात करते पकड़ा था, शर्म और पछतावे में कर ली आत्महत्या

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोलार इलाके में महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना शुक्रवार तड़के 3:30 बजे की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पति ने पत्नी पर दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग होने के आरोप लगाए हैं। सुसाइड से पहले पति और पत्नी के बीच दूसरे युवक से बात करने को लेकर विवाद भी हुआ था। जानकारी के मुताबिक मुस्कान पति अनिल (24) निवासी सर्वधर्म ए सेक्टर गृहिणी थी। मृतका के पति अनिल ने बताया कि शादी के सात साल बाद भी दोनों की कोई संतान थी। पति का आरोप है कि पत्नी दूसरे युवक से फोन पर बात करती थी। उसके साथ पूर्व में भागने का प्रयास कर चुकी थी। हालांकि तब वह समझाइश के बाद घर लौट आई थी। गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात मैंने उसे युवक से फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसी बात को लेकर पत्नी से कहासुनी हुई। तड़के 3:30 बजे मेरी नींद खुली। तब पत्नी का शव पास ही में फांसी के फंदे पर लटका देखा। शव को उतारने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए रवाना कर दिया। पोस्टमार्ट्म के बाद बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त किया

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस को शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मोबाइल फोन का परीक्षण कराएगी। पति के डिटेल बयानों को दर्ज कर लिया गया है। मृतका के मायके पक्ष के डिटेल बयान फिलहाल दर्ज नहीं किए जा सके हैं।

भजन गायक की नर्मदा में डूबकर मौत

- अमरकंटक में फव्वारे की रेलिंग में फंसा पैर; हजारों श्रद्धालुओं के सामने गई जान

अनूपपुर (नप्र)। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में रामघाट पर गुरुवार को भजन गायक राज भदौरिया (22) की डूबने से मौत हो गई। घटना शाम करीब 5.30 की है। राज का पैर नहाते समय नदी में बने फव्वारे की रेलिंग में फंस गया था। गुरु पूर्णिमा होने के कारण घाट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक, राज अपने बड़े भाई अर्जुन भदौरिया और जीजा के साथ स्नान करने आए थे। राज और अर्जुन नदी के बीच बने फव्वारे तक पहुंच गए। पैर फंसने के बाद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वाटर बोट की मदद से रेस्क्यू किया गया। स्थानीय निवासी कृष्णा पाल चौहान ने राज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

मगरमच्छ के हमले से महिला की मौत

- दमोह में जबड़े में दबाकर नदी के दूसरे किनारे तक ले गया; शव एक घंटे बाद मिला

दमोह (नप्र)। दमोह में शुक्रवार सुबह व्यारमा नदी में नहाने गई एक महिला को मगरमच्छ खींच ले गया। महिला को मगरमच्छ के जबड़े में जकड़ा देख लोगों ने शोर मचाया। करीब एक घंटे बाद महिला की लाश मिली। घटना कनिया घाट पटी गांव की है। महिला की पहचान मालतीबाई (40) पति मेघराज सिंह के रूप में हुई है। ग्रामीण प्रहलाद सिंह का कहना है कि मालती एक सहेली के साथ सुबह करीब 6 बजे गई थी। सावन का पहला दिन है, इसलिए उनको जल भी लाना था। उसकी सहेली किनारे पर खड़ी थी। मालती डिब्बे में नदी से पानी भर रही थी, तभी मगरमच्छ ने उनके पैर को जबड़े में भर लिया। मगरमच्छ उनको खींचते हुए नदी के बीचोंबीच ले गया। नदी का बहाव तेज है, इसलिए लोग उसे बचा नहीं सके।

ग्रामीण ने बनाया वीडियो, एक घंटे बाद मिला शव: एक ग्रामीण ने घटना का वीडियो बना लिया। इस बीच सूचना मिलते ही वन विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की सर्चिंग के बाद महिला का शव नदी के दूसरे छोर पर झाड़ियों में फंसा मिला। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर, एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी और छत्रह ईश्वर जरांडे मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वन विभाग के मुताबिक व्यारमा नदी में मगरमच्छों की संख्या बढ़ने के कारण कई चिह्नित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे और मुनादी भी करवाई गई थी। इसके बावजूद लोग ऐसे स्थान तक जा रहे हैं।

युवक की संदिग्ध हालात में मौत

- परिजन ने कहा- अंजान महिला ने दी मौत की सूचना; पुलिस बोली- एक्सीडेंट में जान गई

भोपाल (नप्र)। भोपाल के ईटखेड़ी में चौरसिया ढाबे के सामने युवक की खून से लथपथ लाश मिली है। शव को गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात बरामद किया गया है। पुलिस शुरुआती जांच में एक्सीडेंट से मौत होना मानकर चल रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि मौत की सूचना एक अनजान महिला ने दी। वह मौके पर भी मौजूद थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र सिंह दांगी पुत्र किशन लाल दांगी (38) लांबाखेड़ा शारदा नगर वाइन शॉप पर काम करता था। मृतक के भतीजे रवि दांगी ने बताया कि चाचा की मौत की सूचना एक महिला ने दी। स्पॉट पर पहुंचे तो महिला मौजूद थी। जिसने बताया कि चाचा महेंद्र ने उन्हें लिफ्ट दी थी। बाइक बेकाबू होकर एक गड्ढे में गिरी। इससे चाचा की मौत हो गई। रवि का कहना है, एक्सीडेंट के समय गाड़ी पर महिला मौजूद थी, उसी ने इस बात की पुष्टि की है तो चोटें उसे क्यों नहीं आई।

भोपाल जिला पंचायत की मीटिंग में जर्जर स्कूलों का मुद्दा

सदस्य बोले- कई बिल्डिंग जर्जर, हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा?

भोपाल (नप्र)। भोपाल जिला पंचायत की साधारण सभा की मीटिंग में सरकारी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग का मुद्दा उठा। उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट, सदस्य विनय मेहर, विक्रम बालेश्वर, बिजिया राजौरिया ने यह मुद्दा उठाया। कहा कि कई बिल्डिंग जर्जर है। यहां हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा?

सदस्यों के इस मुद्दे पर डीपीसी आरके यादव ने कहा कि ऐसी बिल्डिंग की जांच करवाई जा रही है। निरीक्षण में डोगरा जागीर में टपकती छत के नीचे बच्चे बैठे मिले। पिपलिया में भी यही स्थिति थी। रात 8 बजे छत की सफाई करवाई। जितने संसाधन है, उनसे काम करवा रहे हैं।

उपाध्यक्ष जाट ने कहा कि सभी स्कूलों का निरीक्षण करें। सदस्य राजौरिया ने कहा कि अभी तो बोल देंगे लेकिन बाद में कोई काम नहीं करेंगे। सदस्य मेहर ने कहा कि पथरिया के स्कूल तालाब में लग रहा है। 3 साल से ऐसा है। 25 साल पुरानी बिल्डिंग है। छत से पानी टपकता है। शासन को मरम्मत करने की बात कही है।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में इसलिए जा रहे कि स्कूल बिल्डिंग जर्जर है। सीईओ इला तिवारी ने कहा कि पथरिया में नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन कोई उपयोग नहीं हो रही। यदि कोई और सरकारी बिल्डिंग है तो बच्चों को शिफ्ट करें।

सदस्य भोलेश्वर ने कहा कि भामरा में स्कूल की दीवार गिर चुकी है। सांप भी निकलते हैं। बावजूद टूटे हुए स्कूल में बच्चों को बैठाया जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है? डीपीसी आप निरीक्षण करें। बच्चे 10 का पहाड़ा नहीं सुना पाएंगे।

बैठक में एसडीएम को बुलाने पर नोकझोंक

बैठक में एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को बुलाने की बात सदस्यों ने उठाई। इसी मुद्दे पर सीईओ तिवारी और फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत के बीच नोकझोंक भी हो गई। सीईओ ने लिखित में प्रस्ताव देने की बात कहीं। इस पर राजपूत ने कहा कि हमने पूर्व में लिखित में दिया था। सदस्य भोलेश्वर ने भी अधिकारियों को बुलाने की बात कही। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचई, कृषि, पीडब्ल्यूडी, आदिम जाति, वन, महिला एवं बाल विकास विभागों की समीक्षा होगी। इससे पहले होने वाली सामान्य प्रशासन समिति की मीटिंग में प्रतिनिधियों की एंट्री नहीं हुई।

वहीं, साधारण सभा की बैठक में अधिकारी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजने का आदेश था, लेकिन कई अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेज दिया।बता दें कि मीटिंग पिछले दो बार टाल दी गई थी। 11 जुलाई की तारीख फाइनल की गई थी। पिछली बैठक के दौरान काफी हंगामा हुआ था। उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शिक्षा, सड़क समेत कई मुद्दों पर अफसरों को घेरा था। बैठक में एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को बुलाने की बात सदस्यों ने उठाई।

पहले सामान्य प्रशासन हुई, फिर साधारण सभा

दोपहर 12 बजे सामान्य प्रशासन समिति की बैठक हुई। इसमें अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर, उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट समेत सदस्य शामिल रहेंगे। वहीं, दोपहर 1 बजे से साधारण सभा की बैठक शुरू हो गई।

इसलिए जरूरी है मीटिंग: जानकारी के अनुसार, मीटिंग ही एक ऐसा प्लेटफार्म होता है, जब सभी विभागों के अफसरों से जिपं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य रूबरू होते हैं। पिछली बैठकों में तो उपाध्यक्ष और सदस्यों की अधिकारियों पर भड़ास भी निकली थी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज करेंगे एक्का पार्क का भूमिपूजन

- इतिहास से भविष्य को जोड़ेगा अत्याधुनिक एक्का पार्क, मछली घर नहीं, अब मछलियों की दुनिया बसेगी
- मछली घर से नये एक्का पार्क का सफर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार 12 जुलाई को भोपाल में बनने जा रहे अत्याधुनिक मछलीघर एक्का पार्क का भूमि-पूजन करेंगे। भोपाल सहित पूरे प्रदेश से भोपाल आने वाले पर्यटकों के ज़हन में मछलीघर की एक खास जगह है। वो पुराना मछलीघर जहां स्कूल की पिकनिक होती थी, माँ-पापा के साथ सैर होती थी, और रंग-बिरंगी मछलियों को देखकर चौंकते, मुस्कराते और कभी-कभी डर भी जाते थे। नीली रोशनी में तैरती सुनहरी मछलियाँ मानो कैनवास पर बनी कोई पेंटिंग थीं। वक्त बीत गया और अब मछलीघर अतीत को साथ में समेटे हुए फिर से भोपाल में एक नई पहचान के साथ लौटने जा रहा है। देश के सबसे सुंदर और आधुनिक एक्का पार्क में से एक भोपाल में आकार लेने जा रहा है।

एक्का पार्क में खास क्या है?

केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, राज्य सरकार का इसमें 15 करोड़ रुपये का सहयोग से 40 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना होगी। एक्का पार्क न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा, बल्कि बच्चों के लिए रोमांच, शिक्षा, शोध और कौतूहल का नया केंद्र भी बनेगा। एक्का पार्क में समुद्री और मीठे पानी की मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां देखने को मिलेंगी। डिजिटल एक्वेरियम, वॉटर टनल, 3डी इंटरेक्टिव जोन, बच्चों के लिए सी-लाइफ लर्निंग सेंटर, रिसर्च सेंटर (मछली पालन की पारंपरिक और नवीन तकनीक की डेमोंस्ट्रेशन यूनिट), मत्स्य सेवा केंद्र (मछली पालकों के प्रशिक्षण के लिए), आंत्रप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इनक्यूबेशन सेंटर, कैफेटेरिया (रंगीन मछलियों का प्रदर्शन और मछली से जुड़े गिफ्ट आइटम) एवं पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण जैसे कार्यक्रम भी एक्का पार्क में उपलब्ध होंगे। एक्का पार्क के जरिए नई पीढ़ी सिर्फ मछलियाँ नहीं देखेगी बल्कि पानी और प्रकृति के प्रति संवेदनशील भी बन सकेगी। इस पार्क का निर्माण भदभदा स्थित मछलीघर में प्रस्तावित है। एक्का पार्क इतिहास और भविष्य के बीच एक पुल बनने जा रहा है। राजधानी भोपाल के लिए यह केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि स्मृतियों के गलियारे में सैर करने जैसा अनुभव होगा। पुराने मछलीघर में हाथों में गुब्बारा लेकर रंग-बिरंगी मछलियों को देखने वाले लोग अब अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उसी जगह फिर लौटेंगे। लेकिन इस बार रोशनी और तकनीक से सजा हुआ एक भव्य एक्का पार्क उनकी नई यादों की शुरुआत करेगा।

मंदाकिनी से दानिश कुंज तक सड़क बनी जानलेवा

तीन महीने से टेंडर पास, नहीं शुरू हुआ निर्माण; लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के मंदाकिनी से दानिश चौराहे के बीच सड़क निर्माण नहीं होने से लोग परेशान हैं। बारिश से सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। कई जगह से डामर पूरी तरह से उखड़ गया है। ऐसे में लोगों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता केपीएस राणा और भोपाल के चीफ इंजीनियर संजय मस्के को कांग्रेस नेता राहुल सिंह राठौड़ ने ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कोलार के मंदाकिनी से दानिश चौराहे तक की 80 फीट सड़क का कार्य एक सप्ताह में शुरू करने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि निर्माण शुरू नहीं होता है तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव करेंगे।

एक दर्जन बड़ी कॉलोनियां, हजारों लोग परेशान

जिस सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, वह भूमिका रेजीडेंसी, सिग्नेचर-99 समेत एक दर्जन बड़ी कॉलोनियों से जुड़ी हैं। वहीं, जेके हॉस्पिटल भी यही है। ऐसे में हर रोज हजारों लोग परेशान होते हैं।

भविष्य के लिए सतत हरित शहरीकरण विषय पर हुआ सत्र

हरित बुनियादी ढांचे का विकास, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, कार्बन क्रेडिट, स्मार्ट सिटी एवं नागरिकों की भागीदारी विषय पर हुई चर्चा

भोपाल (नप्र)। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को हुये सत्र में मध्यप्रदेश ग्रोथ कान्क्लेव 2025 के अंतर्गत 'भविष्य के लिए सतत हरित शहरीकरण' सत्र में इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, हरित बुनियादी ढांचे का विकास, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण स्मार्ट सिटी एवं नागरिकों की भागीदारी विषयों पर विचार मंथन किया। प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री नवनीत मोहन कोठारी ने कहा है कि सरकार नीतियों एवं चुनौतियों को सुदृढ़ करते हुये हरित नगरों का विकास कर सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास जारी है। शहरों का विकास इस तरह से करना चाहिए कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके। सत्र में कार्यकारी निर्देशक सीएसई सुश्री अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा कि समुदाय हरित विकास की योजना बनाने और उसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पर्यावरण को बचाने और टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देने में सक्रिय सहभागिता करते है। अधोसंरचना तत्परता के लिये भवन निर्माण एवं वाहन क्षेत्र में उचित वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये।

रीएनर्जी डायनेमिक्स प्राइवेट के सीईओ और सह-संस्थापक श्री वरुण कराड ने कहा कि भविष्य उन्मुखी शहरों का निर्माण किया जाना चाहिए जो अगले कई सालों तक यथावत रहे। ग्रीन बॉन्ड, कार्बन क्रेडिट एवं पीपीपी मॉडल इस ओर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। वर्बियो इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री आशीष कुमार ने बायो फ्यूल में पीपीपी मॉडल, नीति आधारित समावेशी प्रबंधन विषयों पर चर्चा कर निजी क्षेत्र में तकनीकी अनुभव, प्रमाणित तकनीक एवं प्रमाणीकरण की महत्ता पर ज़ोर दिया गया है। एसएस गैस लैब एशिया के सदस्य आईएफजीई अध्यक्ष नेट जीरो,लघु उद्योग भारती की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री जयंती गोएला ने तीव्र औद्योगिक विकास के दौर में ट्रांज़िशन तकनीकों की आवश्यकता पर जोर देते हुए ऐसी तकनीकों के विकास पर बल दिया जिनसे कार्बन फुटप्रिंट को नियंत्रित किया जा सके। ईकेआई एनर्जी उपाध्यक्ष और वैश्विक व्यापार विकास के प्रमुख श्री सिद्धात गुप्ता ने नेट जीरो लक्ष्य, सस्टेनेबल प्लानिंग, कार्बन क्रेडिट मॉनिटरिंग आदि विषयों पर चर्चा की। सत्र के अन्त में पूर्व लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे शहरीकरण पर अपने विचार रखें।

डिजिटल ट्रांजेक्शन में भारत देश एक नम्बर पर : मंत्री सारंग

- कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को सुविधा और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का साधन

भोपाल (नप्र)। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर जहां एक ओर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, वहीं इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो रहे है। देश के विकास में सरकार के लिये गये निर्णयों में सीएससी का गठन सबसे अग्रणीय निर्णय रहा। आज भारत देश डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में नम्बर एक पर है। मंत्री श्री सारंग ने यह बात सीएससी दिवस के उपलक्ष्य में आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित कार्यशाला में कहीं। इस अवसर पर सीएससी के राज्य प्रमुख श्री अतुलित राय भी उपस्थित थे। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और कल्याण के कार्य किये जा रहे है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पारदर्शिता के साथ योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, इसमें बीएलई की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर व्यक्ति में ईमानदारी और कर्त्तव्य बोध है, इसे जगाने की जरूरत है। सीएससी के माध्यम से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बीएलई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लोगों और सरकार का काम कर रहे।

उनके व्यवहार, आचरण और कार्य पद्धति से व्यवस्था परिलक्षित होती है। बीएलई द्वारा लोगों के किये गये कार्य से उसे पैसों के साथ दुआएं भी मिलती हैं। मंत्री श्री सारंग ने सुझाव दिया कि सीएससी में सुझाव और शिकायत की भी व्यवस्था हो और वर्ष में सीएससी में परफॉर्मेंस और उनके व्यवहार के आधार पर अवार्ड दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन बीएलई का व्यवहार अच्छा रहे उन्हें सम्मानित करें, जिससे दूसरे लोग भी प्रेरित हों। उन्होंने बीएलई से कहा कि सीएससी में सफाई व्यवस्था उसका उन्नयन और नवाचार करने से आपकी साख बढ़ेगी और विकसित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। कार्यशाला में सीएससी पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। उज्जैन, अशोकनगर, डिण्डोरी, दमोह, पन्ना, छिंदवाड़ा के एक-एक बीएलई, छतरपुर, सिवनी, देवास के दो-दो कुल 12 बीएलई उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित किये गये।

संपादकीय

भागवत का इशारा किस ओर?

राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने 75 की उम्र में रिटायरमेंट की बात कहकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है। राजनीतिक हल्कों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भागवत का यह इशारा किसके लिए है? क्या यह इसी साल जीवन के 75 साल पूरे करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए है या फिर खुद मोहन भागवत ने अपने भावी प्लान का संकेत दिया है, क्योंकि वो स्वयं भी इसी साल सितंबर में जीवन के 75 वसंत पूरे कर रहे हैं। या फिर ये संघ और भाजपा में काम कर रहे सभी लोगों के लिए है? अगर भागवत का बयान व्यक्तिशः किसी के लिए भी नहीं है तो फिर इस 'जनरल स्टेटमेंट' का क्या मतलब है? क्या संघ अब नरेन्द्र मोदी के उत्तराधिकारी की खोज में जुट गया है? गौरतलब है कि नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह में भागवत ने कहा कि पचहत्तर साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। वे संघ के दिवंगत कार्यकर्ता मोरोपंत पिंगले के जीवन और उनके योगदान की चर्चा कर रहे थे। भागवत ने पिंगले की निस्वार्थता, विनम्रता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा की। इसी संदर्भ में उन्होंने पिंगले के उस नज़रिए का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने 75 वर्ष की आयु को एक ऐसी सीमा के रूप में देखा, जहां व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंप देना चाहिए। भागवत ने इसे पिंगले की विनम्रता और अगली पीढ़ी को अवसर देने की उनकी सोच के रूप में पेश किया। भागवत ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन्होंने धैर्य, विनम्रता और संघ के प्रति समर्पण का परिचय दिया। भागवत ने मोरोपंत पिंगले के जीवन पर आधारित पुस्तक मोरोपंत पिंगलेः द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस का विमोचन करते हुए कहा कि मोरोपंत जी कहते थे कि पचहत्तर साल के बाद समझ लो कि अब रुक जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र हो गई है। अब दूसरों को काम करने दो। भागवत ने जिस भी मंशा से यह कहा हो, लेकिन जल्द ही उसने राजनीतिक रंग ले लिया। इसका एक कारण यह है कि खुद भाजपा और संघ ने अपने कई पुराने और दिग्गज नेताओं को 75 के बैरियर के तहत मुख्य धारा से बाहर कर घर बिठा दिया। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन आदि प्रमुख हैं। कहने को उन्हें मार्गदर्शन मंडल में भेजा गया, लेकिन उनसे किसी ने कोई मार्गदर्शन लिया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वैसे भी 75 में रिटायरमेंट का अघोषित नियम है, कोई लिखित संकल्प नहीं है। विपक्षी नेताओं, खासकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत कि मोहन भागवत यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया। क्या वे स्वयं इस नियम का पालन करेंगे? हालाँकि,पिछले साल मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ़ किया था कि बीजेपी के संविधान में 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का कोई औपचारिक नियम नहीं है। शाह ने यह भी कहा था कि मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे और वे अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। वैसे भी मोदी पूरी तरह फिट हैं, ऐसे में केवल आयु की बिना पर वो कोई रिटायरमेंट लेंगे या इसके बारे में सोचेंगे भी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। भाजपा और संघ अभी मोदी का कोई विकल्प भी तैयार नहीं पर पाया है। भागवत के बयान के बाद भाजपा और संघ में पीढ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है या नहीं, यह देखने की बात है, लेकिन इससे उत्तराधिकार की लड़ाई तेज हो सकती है।

बिहार में चुनाव से पहले घोषणाओं का मानसून

नजरिया

सुनील कुमार महला

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यह घोषणा की है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा तथा यह आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। पाठकों को बताता चलूं कि बिहार में 60 प्रतिशत जातीय-आर्थिक आरक्षण पहले से ही लागू है। 35 प्रतिशत मूल बिहारी महिलाओं के इस आरक्षण के बाद यह बढ़ कर 74 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा, जिसका सीधा असर अनारक्षित वर्ग पर पड़ेगा जिसके लिए बस 14 प्रतिशत सीटें ही बचेंगी। वर्तमान में राज्य में 18 प्रति. अति पिछड़ा, 12 प्रतिशत अन्य पिछड़ा, 16 प्रति. एससी, एक प्रतिशत एसटी और ओबीसी महिलाओं का 3 प्रति. आरक्षण लागू है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10 प्रति. भी है।

बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जुलाई को मोतिहारी दौरे से पहले एनडीए ने राजद को बड़ा झटका दिया। मोतिहारी के लगभग 200 राजद मुसलमान कार्यकर्ताओं को जदयू ने घर वापसी कराई गई। मोतिहारी के बंजरिया में आयोजित मिलन समारोह में जदयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद खालिद अनवर की मौजूदगी में राजद के 200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पेंशनधारकों के खातों में नई पेंशन राशि भेजी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि हर महीने 400 से 1100 रुपए मिलेंगे। यह राशि जून से लागू की गई है। हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सभी के खाते में चली जाएगी।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यह घोषणा की है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा तथा यह आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। पाठकों को बताता चलूं कि बिहार में 60 प्रतिशत जातीय-आर्थिक आरक्षण पहले से ही लागू है। 35 प्रतिशत मूल बिहारी महिलाओं के इस आरक्षण के बाद यह बढ़ कर 74 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा, जिसका सीधा असर अनारक्षित वर्ग पर पड़ेगा जिसके लिए बस 14 प्रतिशत सीटें ही बचेंगी। वर्तमान में राज्य में 18 प्रतिशत अतिपिछड़ा, 12 प्रतिशत अन्य पिछड़ा, 16 प्रतिशत एससी, एक प्रतिशत एसटी और ओबीसी महिलाओं का 3 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10 प्रतिशत भी है।

बहरहाल,पाठकों को बताता चलूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला (आरक्षण देने का) लिया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि देश में सभी राज्य सरकारें महिलाओं को कुल पदों में अपने-अपने हिसाब से आरक्षण देती रहीं हैं। जैसे कि उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण, यूपी में राज्य सरकार की ओर से 20 फीसदी आरक्षण, केरल-कर्नाटक, तेलंगाना-पंजाब में 33 फीसदी, और त्रिपुरा में 33 फीसदी पद नौकरियों में आरक्षित किए गए हैं। संशोधन संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कुछ समय पहले राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिलाओं को शिक्षक भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। हालांकि , विधि विभाग ने इस प्रस्ताव पर आपत्तियां जताई और फाइल लौटा दी।इसी प्रकार से महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद संसद और विधानसभाओं(विधायिका) की 33 फीसदी सीटों पर महिला आरक्षण की बात कही गई है,जो साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में पास हुआ था। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि बिहार में चार माह के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक प्रकार से महिलाओं पर लगाया गया बड़ा दांव ही कहा जा सकता है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी जीत हासिल कर सके। गौरतलब है कि साल 2005 में महिला सशक्तिकरण की बात करके ही नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। बहरहाल, राजनीतिक दल और उनके नेता यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय में महिला वोटरों की चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका होती है और महिला वोटर नायिका बनकर उभरतीं हैं। स्वयं नीतीश कुमार भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि आज के समय में बड़ी संख्या में महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगी हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तो पुरुषों के मुकाबले 5.24 फीसदी अधिक महिलाओं ने वोट डाले थे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में 59.69 फीसदी महिलाओं ने वोट दिए थे और 26 महिलाएं जीतकर आगे आईं थीं। हालांकि, वर्ष 2015 में 28 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंचीं थीं। नीतीश कुमार जानते हैं कि महिलाओं के वोट हासिल कर वे सत्ता की चाबी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पाठकों को बताता चलूं कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार, ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लाभकारी योजनाओं की राशि भी बढ़ाई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 60 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाया है। इतना ही नहीं,नीतीश कैबिनेट ने सीता मंदिर के लिए ?883 करोड़ की बड़ी राशि देने का ऐलान किया।इसी प्रकार से बिहार में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गई,जिसे जुलाई से मिलने की बात कही गई है। और तो और नीतीश ने राज्य की युवा आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार युवा आयोग की भी घोषणा की है। पाठकों को बताता चलूं कि युवा आयोग इस बात की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि राज्य के युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। चुनावों से पहले उच्च जाति आयोग, अनुसूचित जाति (एससी) आयोग, महादलित आयोग और मछुआरा आयोग का गठन करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले कहीं थी। कहना ग़लत नहीं होगा कि नीतीश कुमार इस प्रकार की घोषणाओं से सामाजिक संतुलन और सियासी समीकरणों को साध रहे हैं। कुल मिलाकर, सच तो यह है कि बिहार चुनाव से पहले जनता दल (यूनाइटेड) ने 'पच्चीस से तीस, फिर से नीतीश' का नारा दे दिया है। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि बिहार देश के उन शुरुआती राज्यों में एक है, जिसने पंचायत और स्थानीय निकायों में आधी आबादी के लिए पचास फीसदी सीटें आरक्षित की हैं और बिहार सरकार के इस कदम ने यहां की स्त्रियों में जबर्दस्त राजनीतिक जागरूकता पैदा की है। नीतीश कुमार ही नहीं, बिहार में अब हरेक राजनीतिक दल विशेषकर महिला वर्ग को व युवाओं को आकर्षित करने में जुट गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस महागठबंधन ने बिहार राज्य में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य महिलाओं को सशक्त करने के लिये 'माई बहिन मान योजना' कैंपेन लॉन्च किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की सम्मान राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इधर, राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और डोमिसाइल के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में, नीतीश सरकार के महिला आरक्षण के इस नीतिगत दांव व अन्य दावों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वैसे भी महिला आरक्षण बिहार जैसे राज्य में एक बड़े सामाजिक बदलाव का वाहक बन सकता है। वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार का महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण का यह फैसला स्वागत योग्य ही कहा जा सकता है, क्यों कि इससे महिलाओं को आगे बढ़ने के सुअवसर प्राप्त होंगे और वे स्वावलंबी, सशक्त बन सकेंगी। समाज से लैंगिक खाई भी कम हो सकेगी, क्यों कि बिहार जैसे राज्य में आज भी बहुत कम महिलाएं ही सरकारी नौकरियों में हैं। चुनाव अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन यदि चुनावों के बहाने से ही समाज में कुछ अच्छा हो रहा है,तो इससे काबिले-तारीफ और बात भला क्या हो सकती है। किसी समाज में यदि कोई महिला आज आगे आती है तो इससे देश व समाज की तरक्की ही होती है। बहुत अच्छा हो यदि अन्य राज्य सरकारें भी महिलाओं के लिए ऐसे विशेष प्रबंध करने के लिए आगे आएं।

शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन के लिए सक्रिय संघ

आयोजन

अवधेश कुमार

लेखक दिल्ली निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजधानी दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक वैसे तो राजनीतिक दलों एवं मीडिया के लिए किसी हलचल मचाने वाले समाचार का कारण नहीं बना, पर इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। संघ ने संगठन की दृष्टि से पूरे देश को 11 क्षेत्र एवं 46 प्रांतों में बांटा है। बैठक में सरसंघचालक, सरकार्यवाह एवं सहसर्यकार्यवाह सहित केंद्रीय पदाधिकारियों , सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, सभी क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक के साथ 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री शामिल हों तो इसका महत्व समझ में अपने -आप आ जाता है। यानी संघ और इससे जुड़े संगठनों का संपूर्ण संघ प्रतिनिधि नेतृत्व की वहां उपस्थिति केवल मिलने जुलने के लिए तो नहीं हो सकती। संघ का गहराई से अध्ययन करने वाले या निकट से उसकी गतिविधियों पर निष्पक्ष दृष्टि रखने वाले जानते हैं कि बैठकों के सभी सत्रों के विषय एवं प्रारुप निर्धारित होते हैं। विरोधियों के तीखे तेवरों के विपरीत बैठक हमेशा शांत संतुलित व्यवस्थित माहौल में संपन्न होता है। इसमें सामान्य दलीय राजनीति पर विचार के लिए गुंजाइश नहीं होती है। जितनी जानकारी है भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बाहर की उत्कंठा के विपरीत यह चर्चा में भी नहीं आया। संघ के वर्ष में कुछ निश्चित आयोजन हैं जिनमें प्रांत प्रचारक बैठक भी शामिल है। मार्च में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक तथा अप्रैल से जून तक प्रशिक्षण वर्गों के संपन्न होने के बाद यह बैठक आयोजित होती है। इसलिए इसमें देश भर के पूरे वृतांत तथा भविष्य के संगठन की योजनाओं पर फोकस रहता है।

वैसे भी संघ का मुख्य फोकस संगठन, समाज जागरण तथा समाज परिवर्तन है तो इसका फोकस वही रहेगा। जैसा हम जानते हैं इस वर्ष विजयादशमी यानी 2 अक्टूबर से संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पिछले काफी समय से आगामी 2 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर 2026 तक इसके आयोजनों और कार्यक्रमों को लेकर गंभीर चर्चा हमारे सामने आते रहे हैं। स्वाभाविक ही इस समय की अधिकतर बैठकों का केंद्र बिंदु शताब्दी वर्ष ही होगा। जितनी जानकारी है संघ अन्य संगठनों या राजनीतिक दलों की तरह शताब्दी वर्ष पर कोई एक बड़ा आयोजन करने की जगह इसका उपयोग संगठन विसृतार, हिंदुत्व केंद्रित विचार को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने तथा समाज परिवर्तन की दृष्टि से कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए कर रहा है। योजना अनुसार नागपुर में 2 अक्टूबर को वार्षिक विजयादशमी उत्सव में सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत की हर वर्ष की तरह उपस्थिति एवं संबोधन के साथ उसी दिन देशभर में शाखा/ मंडल/ बस्ती के स्तर पर उत्सव आयोजित होंगे। विशेष अभियानों के तहत स्वयंसेवक घर-घर जाकर संपर्क करेंगे। गृह संपर्क अभियान के दौरान स्वयंसेवक संघ साहित्य देकर बातचीत करेंगे। सरसंघचालक मोहन भागवत का विशेष संवाद कार्यक्रम चार शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकता, बैंगलुरु में आयोजित होगा , जिसमें आमंत्रित लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे तथा संवाद भी होगा। संघ ने शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन की दृष्टि से पांच परिवर्तन का विचार रखा है जिसमें सामाजिक समरसता,परिवार यानी कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्व का बोध और नागरिक कर्तव्य शामिल है। दरअसल , मोहन भागवत ने 2021 में समाज परिवर्तन की दृष्टि से ये पांच विषय सामने रखे थे और संघ इस पर काम कर रहा है। इससे संबंधित अलग-अलग सामाजिक सद्भाव सम्मेलन युवाओं का परिवारों का तथा इसी दृष्टि से संवाद आदि के सतत् कार्यक्रम हैं। स्वाभाविक ही प्रांत प्रचारक बैठक में कहां-कहां कितने और कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं तथा उनमें अपेक्षित संख्या की कितनी संभावना होगी, व्यवस्था कैसे हो रही है आदि विषय विंदुवार चर्चा में आए। बैठक से निकलकर सभी प्रांत और क्षेत्र प्रचारक कार्यक्रमों की पूर्व तैयारी की दृष्टि से बैठकें, एकत्रीकरण आरंभ कर देंगे। इनकी गहराई से समीक्षा करें तो साफ हो जाएगा कि समाज और सत्ता में व्याप्त विद्रूपताओं की निंदा , आलोचना, विरोध से परे समाज की सहभागिता से सकारात्मक परिवर्तन का उद्देश्य ही इसके पीछे है। जाति भेद से परे हटकर सामाजिक समरसता के अंतर्गत समाज में सद्भाव बढ़े, परिवारों की पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली बने, हममें स्व-बोध यानी अपने राष्ट्र की महान विरासत, महान सभ्यता -संस्कृति -धर्म -अध्यात्म, फोटो में व्याप्त समाज संगठन उपलब्धियां आदि के प्रति गौरव व्याप्त हो, कुटुंब यानी परिवार के सभी सदस्यों- संबंधियों में आत्मीयता व संस्कारों की वृद्धि हो तथा लोग नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएं तो धीरे-धीरे संपूर्ण समाज और देश की स्थिति कितनी सकारात्मक, सहकारी और सशक्त होगी इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। पहले से इन विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं, उनके साहित्य आदि प्रकाशित हैं, बैठकों में भी इन पर मंथन हो रहा है और प्रांत प्रचारक बैठक में संगठन के स्तर पर इसे आगे बढ़ाने की योजना तय हो गई है इसलिए कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जो जितना तय करें सब कुछ उसी के अनुरूप हो जाए और त्वरित लक्ष्यों की प्राप्ति भी। इसलिए यह नहीं कह सकते कि सब कुछ कल्पना के अनुरूप भी हो जाएगा और सारे लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएंगे किंतु उस दिशा में कुछ हद तक सफलता मिलेगी यह निश्चित है। जितनी संख्या में व्यक्तियों के अंदर पांच परिवर्तन के लिए भाव जाएंगे वह अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करेंगे और समाज के स्तर पर जगह-जगह इन सबके सुखद परिणाम आते रहेंगे। वास्तव में संघ शताब्दी वर्ष की योजना ऐसा नहीं है जिन पर एक वर्ष तक काम किया और फिर।। यह सतत आगे बढ़ते रहने के कार्यक्रम हैं। फिर जिन लोगों से सब ज्ञान के दौरान संपर्क होगा उनके आगे शाखों प्रशिक्षकों आदि की दृष्टि से भी उपयोग की योजनाएं हैं। यानी जो जुड़ें वह छूट नहीं इसकी कोशिश भी होगी। त्वरित परिवर्तन तात्कालिक आंदोलनों से होती है किंतु स्थायी सतत् परिवर्तन और प्राप्तियों के लिए अनवरत ऐसे ही समाज के अंदर स्वतः अभियान संचालित होते रहना आवश्यक होता है। संघ की यही कार्य शैली दिखती है।

चूंकि स्थापना के कुछ समय बाद से ही संघ के नियमित हर वर्ष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होते हैं, इसलिए उसे स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में युवा वर्ग उपलब्ध होते हैं। इसी वर्ष आयोजित कुल 100 प्रशिक्षण वर्गों में से 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्वयंसेवकों के लिए आयोजित 75 में 17, 609 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जबकि प्रकार 40 से 60 वर्ष की आयु के 25 वर्गों में 4270 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। इन वर्गों में देश के 8812 स्थानों से स्वयंसेवकों की सहभागिता रही। आप चाहे संघ की कितनी कटु आलोचना करिए किंतु सोचिए, क्या भारत या दुनिया में कोई दूसरा संगठन इस स्तर पर नियमित प्रशिक्षण वर्ग चलाता है? स्वयंसेवकों में केवल शाखा के कार्यक्रम तक का ही प्रशिक्षण नहीं होता उनकी रुचि के अनुसार सेवा या अन्य क्षेत्रों में जो कार्य समाज की दृष्टि से वे कर सकते हैं उनसे जुड़े कुछ निश्चित क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम बनाने योग्य या उन्नयन का प्रशिक्षण मिलता है। बैठक है तो इस बीच देश और दुनिया की घटनाएं भी चर्चा में अवश्य आएंगी। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्र भाषाएं हैं, और संघ का मानना है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। भाषा संबंधी संघ की सोच अनेक बार सार्वजनिक रूप से रखी जा चुकी है फिर भी विरोधी यही कहते हैं कि संघ केवल हिंदी की ही बात करता है। एक बार पुनः स्पष्ट करने के बाद शायद दुष्प्रचार करने वाले बाज आयें।

पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के स्थानीय अनुभवों तथा लोगों की प्रतिक्रियाओं की इससे ज्यादा अधिकृत जानकारी किसी संगठन को नहीं प्राप्त हो सकती। इस फीडबैक से भविष्य में ऐसी चुनौतियों से निपटने को लेकर समाज व संगठन के साथ सरकार के लिए भी कुछ दिशा मिलेगी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का विराट स्वरूप प्रदर्शित हुआ। उससे बने वातावरण को सनातन आध्यात्मिक मूल्यों के साथ हिंदू समाज की एकता के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से क्या हो रहा ,है क्या कर सकते हैं निश्चय ही ये महत्वपूर्ण विषय हैं हर बैठक में इसकी चर्चा हो रही है। डिजिटल माध्यम के नकारात्मक उपयोग से समाज के अंदर बढ़ रही समस्याओं का समाधान कैसे हो इस पर भी चर्चा होने की सूचना है। जैसा ऊपर बताया गया पूरी बैठक संगठन और कार्यक्रमों पर केंद्रित रही, संघ और विविध संगठनों के संगठन से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे, इसलिए इसका प्रतिफल धरातल पर दिखाई देगा।

पुलों की शामत और सरकारी मशीनरी

कटाक्ष

प्रीतम लखवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

यह सर्वथा सत्य है, जो उठा है, खड़ा है या चलायमान है। वह निश्चित ही गिरेगा। इसमें कोई तर्क इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि यह सब क्रियाएं प्रकृति के अधीन है। प्रकृति इन दिनों मनुष्यों के अधीन है। मनुष्य सरकार के अधीन है और सरकार इन्हीं मनुष्यों की निष्ठा भक्ति के अधीन है। पृथ्वी भू-गोल का हिस्सा है। भूगोल हमने पढ़ा है। इसमें नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं तो झरने, खाइयां और कूप भी है। झरने की प्रकृति है कि वह गिरता है। खाइयां गिराने का भाव पैदा करती हैं। पहाड़ खुद भी गिरने और दरकने को आतुर रहते हैं, लेकिन जो निर्मित हैं, वह कैसे गिर सकता है?

गिरने के भाव का उसमें अभाव है, क्योंकि कमीशन के रसायन से उसे मजबूत जोड़ जो मिलता है। भारत में ही पुल गिरते हैं। ऐसा नहीं है। पुल तो बनते-बनते गिर जाते हैं तो बने बनाए भी गिर जाते हैं। सारे इंजीनियर ये माथा खपा रहे हैं कि आखिर ये पुल भारी भरकम कमीशन के सॉल्यूशन से बनाए थे, फिर कैसे गिर रहे हैं। वे इस बात पर भी हैरान हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी में कहां सूत भर की भी कमी रह रही है। वे ठेकेदार पर आंखें तरेर रहे हैं। ठेकेदार बोलता है-माई-बाप आपने जो डिजाइन, जो रेश्यो दिया, उसी से उस पुल का निर्माण किया, जो आत्महंता बन गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।

इतने में एक वयोवृद्ध इंजीनियर, जिसे सेवानिवृत्ति का तमगा अभी हाल ही में थमाया गया था। वहां आ गया, जहां पुल के गिरने पर मातम कम अपनी इंजीनियरिंग पर अधिक रोना-धोना चल रहा था। उसके आने के बाद एक सुसभ्रांत सा दिखने वाला इंजीनियर बोला-महोदय, आप ही बताइए कि आखिर, 100 साल की उम्र साधकर बनाए गए पुल 50 भी पार नहीं कर पा रहे। कुछ बनने से ही पहले गिरने को लालायित रहते हैं। वृद्ध इंजीनियर बोला- इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पृथ्वी ही दोषी है। अब सबके मुंह खुले रह गए और उसमें इत्मीनान की हवा प्रवेश कर आत्मा को ठंडक पहुंचाने लगी। वृद्ध इंजीनियर फिर बोला-फिर भी कुछ एक्सक्यूज हैं तो अपन सब भू-गर्भ शास्त्री के पास चलते हैं। वे सब एकत्र होकर भू-गर्भ शास्त्री के पास पहुंचे। वे अपनी प्रयोगशाला में कुछ न्यू नार्मल करने के चक्कर में बार-बार अपने बाल नोचे जा रहे थे। सभी ने उनको यथा योग्य किया। उन्होंने पलटे बिना ही उन्हें हाथ के इशारे से बैठ जाने को कहा। सभी बैठ गए। भू-गर्भशास्त्री पलटे और उनसे मुखातिब होकर बोले-कैसे आना हुआ। सभी ने कारण बताया। पुल धराशायी हो रहे हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ते। हूं...।

अब भू-गर्भशास्त्री बोले- मैं वही प्रयोग कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अपने हाथ में एक बाल लेकर आकाश की ओर उछाली और वह चंद सेकंड में ही नीचे गिर गई। वे बोले-समझे? सबने नहीं में गर्दन हिला दी। वे फिर बोले-ऐसा है आपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम तो पढ़ा ही होगा, लेकिन पृथ्वी के गिरत्वाकर्षण आपको किसी ने नहीं पढ़ाया।

यह सब पृथ्वी के गिरत्वाकर्षण के कारण ही हो रहा है। जो जितना गिरना चाह रहा है, गिर रहा है। इसमें पुल, मानवता, इंसान, नेता, अधिकारी और मशनरी सब शामिल है। सभी ने समाधान पूछा- भू-गर्भ शास्त्री बोले- जब तक गिरत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त नहीं होगे। यह सब होते रहेगा। सभी अपना सा मुंह लेकर वहां से रवाना हो गए और भू-गर्भ शास्त्री मुस्कान बिखेर कर पुनः लैब में घुस गए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

दिल जो दीवाना था, बाग-बाग हुआ..?

व्यंग्य

दिनेश गंगराड़े

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जीवन में सारे जद्दोजहद के बाद जब मन प्रसन्न होता है तो दिगल बाग-बाग हो जाता है। जिसे यार-दोस्त बकते है हार्ट, गार्डन-गार्डन हुआ ये दिल बड़ी चलायमान,पागल, चंचल, दीवानी,दिलफेंक चींज है।कभी इधर,कभी उधर, कभी किधर धड़कता रहता है। ये दिल दीवाना भी है और परवाना भी,बड़ा कातिल है,पल में तोला पल में माशा,छटे चौमासा करता रहता है उतापा? परिस्थितियां जीवन में कभी अच्छी,कभी बुरी,कभी देती हेडेक तो कभी परोसती सबुरी।

जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में अंडशंड,टोपला भर कर नम्बर लाते है तो मन मयूर खिल उठता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी नहीं समाती,उस खुशी के मारे वो जमीन से एक फीट ऊपर चलने लगता हैं । उसकी चंचलता देखते नहीं बनती,तितली के माफिक वो इधर,उधर,किधर,मन पड़े जिधर मंडराता रहता है। दिल दरबार दहलने,मन मुस्कुराने,कुछ गुनगुनाने लगता है। शरीर,ये लाने,वो लाने (?) को मचल उठता है। मनमाफिक सक्सेस नसीब होने पर मन मदमस्त,बंदा चुस्त हो और उसका दिल आनंदित हो बगीचा-बगीचा हो उठता है किंतु इसके विलोम जब आशा (कोई लड़की का नाम नहीं) के विपरीत, मन के उल्टा घट जाता है तो मन दावानल सा सुलग उठता है,बंजर भूमि सा दिखने लगता हैं,अगला पस्त, सुस्त,लस्त,होकर लगाने लगता है गस्त।

ज्ञानी लोग बक गए हैं कि मन एक पंछी है ।इसे पिंजरे में मत कोंडो, घेरों,वो रुकेगा नही,उसे जितना उड़ाना है उड़ा लो। आजकल का सॉलिड दिल तो इतना मजबूत है कि पिंजरा तोड़कर फुर्र हो जाता है और लोगो को पता भी नही चलता है। आजकल की बेंडी पीढ़ी तो दिल का कहना भी नही टालती है,अपने मर्जी माफिक बेजुलुल हरकतें करती रहती हैं। तुमने उसे नियंत्रित करने, दबाने का दुःसाहस किया तो तुम खुद उल्लू सिद्ध हो जाओगे।इंसान की प्रसन्नता उसके मनमाफिक कार्य होने पर होती हैं तभी वो सेंट-परसेंट खुश होता है।शायर कहते है दिल का यकीन नहीं करना चाहिए ये गिरगिट सा रंग बदलता है।ये किसी पर भी आ सकता है, टूट सकता है, गले पड़ सकता है।ये अनियंत्रित वस्तु है। इसे नियंत्रित करने में सारी उम्र लग जाती है,खप जाती है।

ज्यादा नियंत्रित करने वाले साधु संत बन जाते हैं और जो दिल के कहने में उसके गुलाम बन कर चलते हैं बड़े शैतान,रंगीले,शातिर बन जाते है।दिल पर दिलदार गीतकारों ने कई गाने बड़े दिल से लिखे हैं। नवयुगल प्यार में दिल पर तीर चलाते हैं।एकाध तीर कलेजे में लगता है और प्यार का पौधा पनपने लगता है। इस दिल की तीर से खासी पटती है,दोनों मे गहरी यारी है।जभी तो तीर कलेजे पर लगता है और आदमी सुधर जाता हैं।कई बार बात दिल पर लग जाती है और आदमी गठान बांध लेता है।मर्यादा तोड़ देता है।कई दफा तो कोई बात दिल के आर-पार हो जाती है, जिसे भुला पाना मुश्किल होता है? उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ जाता हैं। जिसके कलेजे पे एरो नही लगता,कोई बात नहीं लगती,चुभती उसे लोग 'निसड़ला' कहते हैं, मोटी चमड़ी का बेदर्दी दिल में कलेजा रहता है या कलेजे में दिल फंसा रहता है। दोनों आपस में आमने सामने रहते हैं। इसका सीधा संबंध दिमाग से रहता है।

दिल से भेजा नही,भेजे से दिल संचालित होता है। जो दिलफेंक लोग रहते हैं उन्हें दिलवाले और जो दिल की नहीं सुनते हैं वो दिलजले रहते हैं? बहुत से दिल के गुलाम होते है,कोई-कोई दिल का बादशाह रहता है। बिरले होते है जो दिल को अपने कंट्रोल में रखते हैं? युवा पीढ़ी दिल के नियंत्रण में, प्रौढ़ लोग दिल से डरे,बुजुर्ग दिल से परे और साधु संत दिल से खरे रहते हैं। मनुष्य के शरीर में दिल की बड़ी कदर है।वो धड़कता है तो सब कुछ है,सुन्न होता है तो सूनी सड़क है,बंद हो गया तो खत्म सब तड़क-भड़क है ! याद रह जाता है लड़क(पन) है। चिकित्सा विज्ञान में भी इसकी धक-धक की कीमत है, इसके भक-भक होते ही व्यक्ति को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया जाता हैं और परिजनों को बिल थमा दिया जाता है। भुगतान नहीं करने पर इस माटी को परिजनों को नही लौटाया जाता है ताउम्र मनुष्य करता है चक-चक,मेहनत कर जाता है थक-थक, फिर कोसता रहता है अपना 'लक-लक'जीते जी वो करता रहता है एक-दूजे पर शक-शक,खुद की ढींग हांकने पर आदमी करता रहता है फक-फक,हमारे उधर गोंडवाना में भूख मरता आदमी हमेशा करता रहता है डक-डक?

यहां डक से तातपर्य और चाहिए और परोसिये। 'मत कमाऊ मीठा भोजन' किस्म के लोग जीवन में उपलब्धियों के नाम पर होते हैं डक (बदख) सार यह है कि जीवन की गाड़ी दिल से ही दौड़ती है। दिल मजबूत हो तो सब ठीक है वरना काय का ठीक भय्या? दिल एक ऐसी जगह है जहां, सारे दर्द और खुशियां रहती हैं।यह एक ऐसा स्थान है जहां,प्रेम और दर्द का संगम होता है। दिल तो बस एक मांस का लोथ है,लेकिन इसमें सारी दुनिया समाई है। यह एक ऐसी चीज है जो, हर किसी के पास होती है लेकिन किसी की भी नहीं है। दिल पर व्यंग्य करना आसान है, लेकिन इसे समझना मुश्किल है। यह एक ऐसी चीज है जो, हर किसी को अपने वश में कर लेती है।दिल की कीमत क्या है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन यह एक ऐसी चीज है,जिसके बिना जीवन सूना है। दिल से अधिक सुरक्षित स्थान नही है संसार में मगर सबसे ज्यादा लोग गायब भी यही से होते है?

विकास की राह में जनसंख्या की चुनौती

मुद्दा

संध्या शास्त्री

हर वर्ष 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस आते ही हम अचानक आंकड़ों और योजनाओं की तरफ देखने लगते हैं। सरकारें जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती हैं और समाज के प्रबुद्ध वर्ग में आबादी को लेकर चर्चाएं होने लगती है। लेकिन यह दिन केवल जनसंख्या वृद्धि को संकट कहने भर का नहीं है – यह दिन सोचने की क्षमता, नीति-निर्माण के दृष्टिकोण, और सामाजिक समावेशन के स्तर का भी मूल्यांकन करने का अवसर है।

भारत आज विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 2024 तक भारत की जनसंख्या 1.43 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। यह संख्या अकेली नहीं है; यह हमारे सामाजिक और संसाधनात्मक ढांचे पर एक गंभीर दबाव बन चुकी है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत ने यह स्थिति पाई है, लेकिन क्या यह उपलब्धि है या चुनौती – इसका उत्तर सबको अपने आसपास के जीवन से मिल सकता है। क्या हम इस बढ़ती जनसंख्या को संभालने के लिए मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से तैयार हैं? क्या हमारी सोच, हमारी योजनाएं और हमारी व्यवस्थाएं उतनी ही विकसित हुई हैं, जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है?

जनसंख्या को अक्सर एक अवसर की तरह देखा जाता है – कहा जाता है कि भारत की 66 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग में है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के लिए पूंजी का काम कर सकती है। लेकिन यह लाभ तभी मिलेगा जब यह जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो। यदि संसाधनों और व्यवस्थाओं में समरसता नहीं होगी, तो यही विशाल जनसमूह असमानता, बेरोजगारी और असंतोष का कारण बन जाएगा। यह भी तथ्य है कि देश के 23 प्रतिशत युवा आज भी बेरोजगारी, अशिक्षा या प्रशिक्षण से बाहर हैं। लगभग 14.9 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। यह केवल आंकड़े नहीं हैं, ये भविष्य के दरवाज़ों पर दस्तक देने वाली वास्तविकताएँ हैं। जिन्हे दर किनार नहीं किया जा सकता है ।

बढ़ती जनसंख्या का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ा है। शहरीकरण और औद्योगीकरण की अंधी दौड़ में पिछले पंद्रह वर्षों में देश के 13 लाख हेक्टेयर से अधिक वनक्षेत्र औद्योगिक परियोजनाओं को सौंपे जा चुके हैं। यह प्रक्रिया केवल जंगलों की कटाई नहीं, बल्कि जीवनशैली और पारिस्थितिकी दोनों की तबाही है। भारत के 14 शहर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने गए हैं। दिल्ली, पटना, कानपुर, गाजियाबाद, भिवंडी – ये केवल नाम नहीं हैं, वायुप्रदूषण के प्रतीक बन चुके हैं। नदियाँ मृतप्राय हैं, तालाब पाटे जा रहे हैं और भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 प्रमुख शहरों में 2030 तक भूजल समाप्त हो सकता है। यह संकट केवल पर्यावरण का नहीं, हमारे अस्तित्व का भी है।

जनसंख्या वृद्धि से जीवन स्तर पर भी गंभीर असर पड़ा है। 'रोटी, कपड़ा और मकान' हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन क्या ये मूलभूत सुविधाएं सभी को उपलब्ध हैं? 13.5 करोड़ लोग आज भी पक्के मकान से वंचित हैं। लगभग 19 करोड़ भारतीय कुपोषण के शिकार हैं। झुग्गियों में रहने वालों की संख्या 70 लाख से अधिक हो चुकी है, जिनके पास स्वच्छ जल, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। भारत में आज भी करीब 1.8 करोड़ लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। यह स्थिति केवल बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं दर्शाती, बल्कि यह हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं और विकास की दिशा पर प्रश्नचिह्न लगाती है। हर वर्ष लाखों लोग गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। लगभग 90 लाख लोग प्रतिवर्ष शहरों की ओर आते हैं, रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की उम्मीद में। परंतु शहरों की स्थिति भी दयनीय है। वे पहले से ही भीड़ से घिरे हैं, बुनियादी सेवाएं चरमराई हुई हैं और नई आबादी को समाहित करने के लिए न योजनाएं हैं, न संसाधन। पलायन करने वाले लोग अधिकतर दिहाड़ी मजदूर, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, घरेलू सहायक या रिक्शा चालक बनते हैं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं असुरक्षित परिस्थितियों में काम करती हैं और उनका जीवन अस्थायित्व के दायरे में सिमट जाता है।

यदि इस समग्र परिप्रेक्ष्य में हम भारत के आदिवासी इलाकों की बात करें, तो तस्वीर और भी मर्मस्पर्शी हो जाती है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ये समुदाय प्राचीन, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े रहे हैं, लेकिन आधुनिक विकास की दौड़ में सबसे अधिक हाशिए पर इन्हें ही रखा गया है। मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित आदिवासी क्षेत्र आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आदिवासी बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और अशिक्षा की दर सामान्य से बहुत अधिक है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्टें बताती हैं कि आदिवासी महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के समय आवश्यक चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल पाती। कई इलाकों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने के लिए दस से पंद्रह किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। बच्चों की टीकाकरण दर और स्कूली शिक्षा के आँकड़े भी निम्न हैं। आदिवासी बहुल जिलों में लगभग 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं।

साथ ही, पर्यावरणीय दोहन और औद्योगिक विस्तार ने आदिवासियों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। खनन, बाँध, और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने लाखों आदिवासी परिवारों को उनके पैतृक गाँवों से विस्थापित किया है। वर्ष 2006 में लागू वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को उनकी जमीन और जंगल पर अधिकार देने का वादा किया गया था, लेकिन 2024 तक लगभग 12 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका मामला अब भी लंबित है। जिनके लिए जंगल जीवन का पर्याय था, वे आज कागज़ी युद्ध में उलझ कर रह गए हैं।

शहरों में भी आदिवासी परिवार बेहतर जीवन नहीं पा सके हैं। वे छोटे-मोटे कामों में लग गए हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और परंपराएँ शहर की दीवारों में दबती जा रही हैं। स्त्रियाँ घरेलू कामगार बन गई हैं। उनकी परंपरा, कला, ज्ञान और प्राकृतिक जुड़ाव को न तो शिक्षा व्यवस्था समझ पाई है, न शासन की योजनाएं।

आज भी भारत के कई हिस्सों में जनसंख्या नियंत्रण एक वर्जित विषय है। पुरुष नसबंदी को लेकर सामाजिक झिझक अब भी बहुत प्रबल है। स्थायी गर्भनिरोध के लगभग 90 प्रतिशत उपाय महिलाओं पर ही लागू होते हैं। यह केवल स्वास्थ्य या व्यवस्था की नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता की समस्या है। महिलाओं को आज भी शिक्षा, रोजगार और निर्णय प्रक्रिया में बराबरी नहीं मिलती। देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी मात्र 25 प्रतिशत है। घरेलू कार्य को अब भी 'काम' नहीं माना जाता। निर्णय लेने वाले मंचों पर महिलाओं की संख्या नगण्य है। शिक्षा की दर भले ही बढ़ी हो, परंतु सोच अब भी उस स्तर पर नहीं पहुँची है जहाँ हम एक समान समाज की कल्पना कर सकें। महिलाएं अभी भी निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखतीं। एक 'कामकाजी महिला' आज भी समाज में असामान्य घटना के रूप में देखी जाती है, जबकि यह उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि कोई एक योजना, नीति या कानून इस संकट का समाधान नहीं कर सकता। आवश्यकता है – सोच के पुनर्निर्माण की, उस चेतना की जो हर नागरिक को समान अवसर, गरिमा और सम्मान के साथ देखे। परिवार नियोजन को स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं, मानव अधिकार के रूप में देखना होगा। महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, नीति-निर्माता की भूमिका में लाना होगा। आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं को उनके सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भ में डिजाइन करना होगा। शिक्षा केवल साक्षरता नहीं, बल्कि वैचारिक आज़ादी का माध्यम बननी चाहिए।

अगर हम हर स्त्री, हर बच्चे, हर आदिवासी, हर नागरिक के अधिकार और गरिमा की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक अवसर नहीं, बल्कि एक बोझ बनती जाएगी। हैं। यह दिन सिर्फ आंकड़ों को देखने या सरकारों की योजनाओं की समीक्षा का अवसर नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है – सामूहिक आत्ममंथन की और यह जानने की कि क्या हम एक जीवंत, विवेकशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक कोई भी जनसंख्या लाभ नहीं दे सकती। सोच को बदलना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अब समय है कि हम सोचें – हम कहाँ जा रहे हैं? और उससे भी ज़रूरी यह है कि हम यह तय करें – हमें कहाँ जाना चाहिए।

प्लास्टिक से विनाश, कागज से समाधान

विश्व पेपर बैग दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इस गंभीर समस्या का एक सशक्त समाधान है 'पेपर बैग'। पेपर बैग शत-प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ ही हफ्तों में स्वयं विघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। वे न तो समुद्री जीवों के लिए खतरा हैं, न ही भूजल या वायु प्रदूषण के कारक। पेपर बैग न केवल पर्यावरण-अनुकूल हैं बल्कि आज एक बड़ा आर्थिक अवसर भी बनते जा रहे हैं। भारत सहित कई देशों में पेपर बैग निर्माण का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो रहा है, जो न केवल हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रोजगार भी पैदा कर रहा है। आज विभिन्न स्टार्टअप और नवाचारों के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का निर्माण हो रहा है। भारत में डीआरडीओ ने कुछ निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्लास्टिक के स्थान पर खाद्य-ग्रेड पौधों से बनने वाले बैग विकसित किए हैं, जो केवल 90 दिनों में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इन बैगों का डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये न केवल उपयोगी हैं बल्कि जानवरों के लिए भी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार, कनाडा, इजरायल, डेनमार्क जैसे देशों में घास, ताड़ के पत्ते, पराली, कपास और चुकंदर की खोई से जैव-प्लास्टिक तथा बायोपैकिंग सामग्री का निर्माण हो रहा है। यह सामग्री सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है तथा इस्तेमाल के बाद कंपोस्ट बन जाती है।

प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध वैश्विक चेतना के प्रतीक और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रतिवर्ष 12 जुलाई को 'विश्व पेपर बैग दिवस' मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर प्रेरित करना है ताकि पृथ्वी को प्लास्टिक के कहर से बचाया जा सके। दरअसल प्लास्टिक की थैलियां आज जिस भयावह रूप में हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं, उस पर नियंत्रण के लिए पेपर बैग एक मजबूत समाधान बनकर उभरा है। दुनिया में हर साल 500 अरब से भी अधिक प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है, जो न केवल हमारी सड़कों, नालियों, नदियों और समुद्रों को भर देता है बल्कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संकट और मानव स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को भी जन्म देता है। प्लास्टिक बैग इतने खतरनाक होते हैं कि समुद्री जीव-जंतु इन्हें भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। समुद्री पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियां प्लास्टिक खा रही हैं, वहीं 250 से अधिक प्रजातियों को प्लास्टिक में उलझे हुए देखा गया है। समुद्री शेरों और सील की कई प्रजातियों में आठ प्रतिशत तक की उलझाव दर देखी गई है। यह स्पष्ट संकेत है कि प्लास्टिक बैग केवल कचरा नहीं बल्कि धरती पर एक घातक आपदा बन चुके हैं।

प्लास्टिक की थैलियां पारदर्शी, सस्ती, हल्की और सुविधाजनक होती हैं लेकिन इनका पर्यावरणीय मूल्य अत्यंत महंगा है। ये नालियों को जाम करती हैं, जिससे शहरी बाढ़ की समस्या बढ़ती है। खेतों में प्लास्टिक थैलियों की मौजूदगी मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती है और जल के रिसाव को रोकती है, जिससे भूजल पुनर्भरण की दर में कमी आती है। प्लास्टिक कई शताब्दियों तक नष्ट नहीं होता और इसके जलाने से जो रसायन निकलते हैं, वे हवा और वातावरण को जहरीला बना देते हैं। यही कारण है कि अब इस पर गंभीर चिंता जताई जा रही है और दुनिया के कई हिस्सों में इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है। भारत में भी इस दिशा में प्रयास किए जा चुके हैं। कई राज्य सरकारों ने प्लास्टिक पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध' जैसे कदमों से इस समस्या के समाधान की कोशिशें हो रही हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रतिदिन लगभग 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 10 हजार टन का कोई निस्तारण नहीं होता। यही वह कचरा है, जो अंततः हमारे जलस्रोतों और समुद्रों तक पहुंचकर पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाता है।

इस गंभीर समस्या का एक सशक्त समाधान है 'पेपर बैग'। पेपर बैग शत-प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ ही हफ्तों में स्वयं विघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। वे न तो समुद्री जीवों के लिए खतरा हैं, न ही भूजल या वायु प्रदूषण के कारक। पेपर बैग न केवल पर्यावरण-अनुकूल हैं बल्कि आज एक बड़ा आर्थिक अवसर भी बनते जा रहे हैं। भारत सहित कई देशों में पेपर बैग निर्माण का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो रहा है, जो न केवल हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रोजगार भी पैदा कर रहा है। आज विभिन्न स्टार्टअप और नवाचारों के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का निर्माण हो रहा है। भारत में डीआरडीओ ने कुछ निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्लास्टिक के स्थान पर खाद्य-ग्रेड पौधों से बनने वाले बैग विकसित किए हैं, जो केवल 90 दिनों में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इन बैगों का डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये न केवल उपयोगी हैं बल्कि जानवरों के लिए भी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार, कनाडा, इजरायल, डेनमार्क जैसे देशों में घास, ताड़ के पत्ते, पराली, कपास और चुकंदर की खोई से जैव-प्लास्टिक तथा बायोपैकिंग सामग्री का निर्माण हो रहा है। यह सामग्री सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है तथा इस्तेमाल के बाद कंपोस्ट बन जाती है।

भारत में भी कई स्टार्टअप केले और बड़े पत्तों से खाद्य पैकेजिंग का विकास कर रहे हैं। यह पारंपरिक भारतीय ज्ञान का पुनरुद्धार भी है, जहां पहले पत्तलों और दोने का चलन था। इन प्राकृतिक साधनों से बनी पैकेजिंग सामग्री न केवल पूर्णतः जैविक होती है बल्कि स्थानीय किसानों और हस्तशिल्पियों के लिए एक आय का स्रोत भी बनती है। वहीं दूसरी ओर, प्लास्टिक की थैलियों का स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। जब हम प्लास्टिक में पैक खाद्य सामग्री का सेवन करते हैं तो उसमें मौजूद हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि प्लास्टिक पैकेजिंग में मौजूद बिस्फिनॉल-ए (बीपीए) और फथेलेट्स जैसे रसायन गैस, हार्मोन असंतुलन, प्रजनन संबंधी समस्याओं, पेट की बीमारियों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह खतरा विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए और भी अधिक है। भारत की स्थिति को देखें तो पॉलीथीन की थैलियों ने न केवल शहरी इलाकों की साफ-सफाई व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी यह संकट गहराता जा रहा है। गांवों की गलियों से लेकर खेतों तक प्लास्टिक के टुकड़े बिखरे दिखाई देते हैं, जो मवेशियों द्वारा निगले जा रहे हैं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। विभिन्न पशु चिकित्सकीय अध्ययन बताते हैं कि हर साल हजारों गायें और भैंसें प्लास्टिक खाने के कारण मर जाती हैं।

इन स्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम न केवल सरकारी प्रतिबंधों और योजनाओं पर निर्भर रहें बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी जिम्मेदारी लें। हमें अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े के थैले, जूट बैग, पेपर बैग, स्टील या तांबे की बोतलों का उपयोग बढ़ाना होगा। स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों और बाजारों में 'नो प्लास्टिक' अभियान को एक आंदोलन की तरह फैलाना होगा। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में सोच सके। विकसित देशों में अब 'जीरो वेस्ट शॉपिंग' की अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जहां ग्राहक अपने साथ खुद के कंटेनर और थैले लाकर खरीदारी करते हैं और इस तरह प्लास्टिक पैकेजिंग से बचते हैं। भारत में भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ शहरी क्षेत्रों में अब ऐसे स्टोर खुल रहे हैं, जहां ग्राहकों को थैला या डिब्बा लाना आवश्यक होता है। यह न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी है बल्कि उपभोक्ताओं को अपने कचरे की मात्रा का भी आकलन करने की आदत डालता है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु संकट, जैव विविधता हानि और पर्यावरणीय विषाक्तता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब एक साधारण कागज का थैला इन समस्याओं से लड़ने में एक बड़ा हथियार बन सकता है। यह न केवल प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोगी है बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतीक भी है, जो प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की ओर बढ़ रही है। इसलिए सरकारों को भी चाहिए कि वे पेपर बैग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करें। छोटे स्तर पर पेपर बैग बनाने वाले कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष सहयोग देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। साथ ही प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माने और सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सही मायनों में विश्व पेपर बैग दिवस का उद्देश्य एक चेतावनी है कि यदि हम अभी भी नहीं संभले तो पृथ्वी पर जीवन का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। यह एक आह्वान है कि हम अपनी आदतें बदलें, अपने उपभोग की प्रवृत्तियों पर लगाम लगाएं और एक ऐसे समाज की रचना करें, जहां विकास और पर्यावरण संतुलन में हों। जब हम एक पेपर बैग को थामते हैं, तब हम केवल सामान नहीं उठाते बल्कि हम एक जिम्मेदारी उठाते हैं धरती को बचाने की।

पानीपुरी - एक अधूरी कहानी

आज विश्व पानीपुरी दिवस

हेमंत मुक्तिबोध

उस दिन, याने कि 12 जुलाई को विश्व पानी पूरी दिवस था। ईमान से कहूं तो मुझे इसका जरा भी इल्म नहीं था। अन्यथा सभी चटोरों, पेटुओं, भुक्खड़ों और खवैयों को इस विलक्षण दिवस पर हार्दिक बधाई देने में इतना विलंब क्यों करता ? वो तो हुआ यों कि पिछली बस्ती में रहने वाले जगनमोहन का बेटा छिद्दू दो दिन मेरी गाड़ी साफ करने नहीं आया। तीसरे दिन उसने बताया कि शहर के एक तीन सितारा होटल के इंडियन कुजिन के मेन्यू में उस खास दिन पर पानीपुरी शामिल की गई थी। रोज गर्ल्स कॉलेज के सामने खोमचा लगाने वाले उसके पिताजी ने इक्कीस फ्लेवर वाली पानीपुरी का वहां स्टाल लगाने का मौका हथिया लिया था। छिद्दू का असली नाम तो अंशुल था। उसकी मां उसे अंसुल कहके बुलाती थीं। लेकिन पानीपुरी की पूरियों में आलू भरने के लिए उंगली से छेद करके अपने पिता को देने का काम वो इस तेजी, लयकारी और नफासत से किया करता था कि बस्ती के लोग उसे छिद्दू के नाम से बुलाने लगे थे। उसी ने बताया कि वो दिन खास इसलिए था कि गूगल बाबा ने उसे विश्व पानीपुरी दिवस घोषित कर दिया था।

यह जानकर मेरा भी सीना 56 इंच का हो उठा कि हमारी पानीपुरी अब लोकल से ग्लोबल हो गई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये उन सभी स्वादाभिलाषियो याने कि चटोरों की ज़िद, जीवट और जिजीविषा का परिणाम है, जिन्होंने अपने हाजमे और हाजत की परवाह किए बगैर पानीपुरी के प्रति अपने जुनून को हमेशा ज़िंदा रखा और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया।

इसीलिए उन सभी पानीपुरी प्रेमियों को शुभकामनाएं जो निरंतर बिना गिने पानीपूरी को पूरी उदारता से उदरस्थ करते रहते हैं। हींग के पानी से ठस्का लगे तो इमली के पानी से ठस्के के दांत खट्टे करते रहते हैं। पर किसी भी हालत में मैदान नहीं छोड़ते। खट्टे दांतों की सिहरन को पुदीने के पानी से दूर करना आयुर्वेद सम्मत है या नहीं इस बहस में वे नहीं उलझते। इससे पहले कि खट्टे दांत उनका हौसला पस्त करने लगें, वे पुदीने के पानी से भरी एक बड़ी सी पूरी का गोला बरसा कर खट्टासुर को धराशायी कर देते हैं। पुदीने का पानी आयुर्वेद के निष्कर्ष के अनुरूप पेट की जलन को ठंडक पहुंचा ही रहा होता है कि इसी बीच जीरे और कच्चे आम वाली पूरी इठलाती हुई आती है और बड़ी ही नजाकत से उनके मुखारविंद में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में पानीपुरी लवर्स के परितृप्त चेहरे जिस आनन्दानुभूति को अभिव्यक्त करते हैं वह वर्णनातीत है।

मेरी गुज़ारिश है कि पानीपुरी को ऐसाङ्कवैसा न समझा जाए। ये बड़ी महिमावान है। ये सर्वत्र और सर्वसुलभ है। सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी। ये समाजवादियों से भी ज़्यादा पक्की समाजवादी है। ये बहुरूपी, बहुआयामी और बहुनामधारी है। कढ़ाई में फूल गई तो फुल्की है। नहीं फूली, तो पापड़ी है। इसके बावजूद इसका मूलभूत तत्व अक्षुण्ण और सर्वत्र समान है। ये जहां भी गई, अपना स्वत्व साथ लेकर गई। कहीं ये पताशा है, कहीं फुचके। कहीं पुचका तो कहीं फुल्की। कहीं गोलगप्पा तो कहीं गुपचुप। वैसे गुपचुप नाम पर मेरी विनम्र असहमति है। इसकी तासीर से ये नाम मेल नहीं खाता। इसे खाने के साथ भी, खाने के बाद भी, कुछ भी गुपचुप नहीं रह सकता। ये स्वभावतः सामाजिक और सार्वजनिक व्यंजन है। फुल्की एक ऐसा व्यंजन है जो स्वर को भी उत्प्रेरित करता है। ये मानव के नश्वर शरीर में यातायात की समस्या के निदांन के लिए 'मार्गावरोध' दूर करता है। इसके सेवन से पदार्थ की तीनों अवस्थाएं मानव शरीर में गति और ऊर्जा को प्राप्त करती हैं जिसकी उसे आगम से निर्गम तक यथासमय और यथास्थान अनुभूति होती रहती है। इसके भोक्ता को ये अनुभूति हमेशा सचेत और सक्रिय बनाए रखती है। परोपकार की भावना के वशीभूत होकर कभी कभी इसका भोक्ता अपनी इस दिव्य अनुभूति की अदृश्य और अश्रव्य (यदा कदा श्रव्य भी) अभिव्यक्ति करता है जिससे उसके आसपास के लोगों को भी इसकी अनुभूति हों जाती है। याने, पानीपुरी अपने भक्तों में सर्वेपि सुखिनः संतु की सर्व कल्याणकारी भावना को भी जगाए रखती है।

इसकी कई विशेषताएं हैं। ये पंथनिरपेक्ष, आयुनिरपेक्ष, लिंगनिरपेक्ष व्यंजन है। लगभग पूरी तरह कैलोरी मुक्त होने के कारण विशेष रूप से ये 'आगत यौवनाओं' से लेकर 'विगत यौवनाओं' तक सबकी प्रिय है। इसका प्रेम उम्र की सीमा और सामाजिक बंधनों से मुक्त है। शादी के रिसेप्शन में या चाट की दुकानों में जब तक इसका पात्र हाथों में नहीं आ जाता तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा का संस्कार प्रदान करना इसकी अतिरिक्त विशेषता है। इसे खाना, इसे बनाने से अधिक कौशल की मांग करता है। इसे खाना एक कला है, करतब है, कार्रवाई है। अपने वस्त्रों को इसके प्रेम से बचाने के लिए एक विशिष्ट अभ्यास और कौशल की दरकार होती है। चूंकि कर्म का कौशल ही योग है इसलिए इसमें योग भी है और अध्यात्म भी। लय भी है और संतुलन भी। अद्वैत, अध्यात्म का आधारभूत सिद्धांत है। पानीपुरी खिलाने वाले और खाने वाले में क्रमशः बढ़ता अद्वैत, बनाने, खिलाने, खाने और खिलखिलाने की इस पूरी प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक आयाम प्रदान करता है। मटके में डुबा कर इसे चटपटे पानी से भरने और चपलता से भोक्ता के मुखारविंद में प्रविष्ट करवा देने तक की प्रक्रिया लय और संतुलन की लाजवाब मिसाल है।

चमत्कारिक बात तो ये है कि चौपालों, चबूतरों और चौराहों की चिल्लपों के बीच भी ये संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, लय कभी टूटती नहीं और इसकी चाह कभी मिटती नहीं। इसीलिए पानीपुरी सर्वत्र है, सर्वार्थ है, सर्वप्रिय है, सर्वसुलभ है। कितनी भी कही जाए, इसकी कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी। इसकी महिमा अपरंपार है और इसकी कथा अनंत। इसलिए इसकी कहानी को यहीं छोड़िए और खोमचे की ओर बढिए। छिद्दू वहां इंतजार में है।

(नोटः इस लेख को पढ़ने के बाद संयम न रखकर अधिक पानीपुरी खाने के उपरांत पेट खराब होने पर लेखक जिम्मेदार नहीं होगा!)

भाषाई राजदूत मध्यप्रदेश

सामयिक

प्रो. मनोज कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

मध्यप्रदेश के भौगोलिक गठन को लेकर निराश होता था. लगता था कि देश का ह्रदयप्रदेश कहलाने वाले मध्यप्रदेश की कोई एक भाषा, एक संस्कृति नहीं है. यहाँ तक कि दो दशक पहले मध्यप्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है. लेकिन आज लग रहा है कि मेरा मध्यप्रदेश सचमुच में अनुपम है. अलग है और एक धडक़ते दिल की तरह वह भारत का प्रतिनिधि प्रदेश है. यहाँ भाषा और संस्कृति को लेकर कोई विवाद नहीं है. वह बाँहें पसारे खुले मन से सबका स्वागत कर रहा है. यह प्रदेश भावभूमि है. यहाँ देश के सभी प्रदेशों के भाषा-भाषी निवास करते हैं. उनकी संस्कृति और संस्कार को मध्यप्रदेश के रहने वाले स्वागत करते हैं. सच कहा जाए तो देश दिल मध्यप्रदेश भाषा और संस्कृति का राजदूत है. आज जब भाषा विवाद चरम पर है तब मध्यप्रदेश मुस्करा रहा है. शायद वह कह रहा है कि आओ, मुझसे सीखो कि भारत की बहुभाषी और संस्कृति को कैसे सम्मान दिया जाता है. पंडित नेहरू ने कभी मध्यप्रदेश को बेडौल प्रदेश कहा था लेकिन इसी बेडौल भू-भाग वाला मध्यप्रदेश भारत का आदर्श प्रदेश के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है.

मध्यप्रदेश का मुआयना करें तो आपको कई रीजन मिलेंगे. इनमें मालवा, महाकोशल, विंध्य, बुंदेलखंड, चंबल और कभी छत्तीसगढ़ भी इसका हिस्सा हुआ करता था. अपनी स्थापना के सात दशक बाद भी कभी यहाँ भाषा विवाद सुलगा नहीं और ना ही संस्कृति को लेकर कोई विवाद हुआ. बहुभाषी साहित्य को जितना बड़ा मंच मध्यप्रदेश में मिला, वह कहीं और नहीं. भारत के इस प्रतिनिधि प्रदेश में हर प्रदेश का स्वागत है. भरोसा ना हो तो एक बार भारत भवन के आयोजन का कैलेंडर उठा कर देख लीजिए. प्रतिवर्ष देश के सभी राज्यों की कलाओं का प्रदर्शन होता है, भागीदारी होती है. विविध भाषाओं के साहित्य पर चर्चा होती है. यही नहीं, मध्यप्रदेश की साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन में हर भाषा को स्थान दिया गया है. मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद में मराठी, सिंधी, पंजाबी, भोजपुरी अकादमी है तो मध्यप्रदेश ने माँग की कि हम सिंधी की शिक्षा देंगे तो हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में इस पाठ्यक्रम की अनुमति मिल गई और जल्द ही औपचारिक शिक्षा भी शुरू हो जाएगी. देश के ह्दयप्रदेश का ह्दय हर प्रदेश के लिए धडक़ता है और यही कारण है कि मध्यप्रदेश राजभवन में एक-एक कर विभिन्न राज्यों का स्थापना दिवस उत्सव मनाया जाता है.

भारत देश बहुभाषी संस्कृति और साहित्य का देश है. भाषा और बोली की यह खूबसूरती है कि हम सब मिलकर सतरंगी दुनिया गढ़ते हैं. गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि मध्यप्रदेश भारत की इस छवि का प्रतिनिधि प्रदेश है. राजदूत है जो शांति, समन्वय और सद्भाव के संदेश को भेजता है. राज्य सरकार के अथक कोशिश से मध्यप्रदेश में लगातार फिल्मों, टीवी सीरियल्स और ओटीटी प्लेटफार्म के लिए निर्माण हो रहा है. इमदाद और मदद दोनों फिल्ममेकर्स को मिल रहा है लेकिन परदे पर कहीं एक पंक्ति नहीं दिखता 'धन्यवाद मध्यप्रदेश', बावजूद इसके हम उनका हमेशा से स्वागत करने तिलक रोरी लिए खड़े होते हैं. वर्तमान सरकार तो पीले चावल लेकर प्रदेश-दर-प्रदेश जा रही है कि आइए, हमारे प्रदेश में उद्योग लगाइए. मध्यप्रदेश इतना कर रहा है लेकिन सवाल है कि क्या मध्यप्रदेश जैसी सुंदर, सुखद पहल कोई और कर रहा है? क्या हम सब भारत माता के लाल नहीं हैं? इस पर विचार करना जरूरी हो जाता है. देश में छिड़ा भाषा विवाद नया नहीं है. समय-समय पर यह विवाद होता रहा है. इसमें सबसे अहम बात यह है कि भाषा का विरोध अर्थात हिन्दी का विरोध. हर प्रदेश की एक भाषा है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है. इसी बहुभाषी संस्कृति से भारत की विश्व में अलग पहचान है.

भाषा विवाद के संकट बड़े हैं. वह ना केवल राष्ट्रीय एकता और संप्रुभता को संकट में डालता है बल्कि रोजी-रोजगार पर भी असर होता है. इस विवाद में एक उपाय यह भी हो सकता है कि आक्रामक होने के बजाय भाषा प्रशिक्षण केन्द्र हर राज्य में आरंभ कर दे. जिन्हें यह भाषा नहीं आती, उन्हें सीखने और समझने का अवसर दे. इससे शायद कोई रास्ता सुंदर निकल आए. रास्ता ना सही, एक पगडंडी तो मिल ही जाएगी. वैसे भी हिन्दी की खूबसूरती देखिए जिसका आप विरोध कर रहे हैं, वही आपको एक कर रही है.

केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा, जिलाध्यक्ष निलेश भारती ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साधु-संतों, गुरुजनों का किया सम्मान

भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले के प्रत्येक मंडलों में गुरुओं का किया गया सम्मान

धार। श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल पर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर, विधायक नीना विक्रम वर्मा भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने शाल श्रीफल भेंट कर साधु संतों गुरुओं का किया सम्मान। मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजन अर्चना करते हुए देश के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर ने माण्डव श्रीराम मंदिर पर महामंडलेश्वर डॉ. नरसिंहदास जी महाराज तथा बदनावर विधानसभा क्षेत्र ग्राम छायन आश्रम में संत पूजन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती और विधायक नीना विक्रम वर्मा ने धार स्थित श्री नित्यानंद आश्रम में अवधूत पूज्य गुरुदेव नित्यानंद बापजी के दर्शन कर पूजन किया।

गुरु ही हमें मार्ग दिखाते हैं: महंत निलेश भारती

भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व मानव के जीवन में होता है। गुरु हमें मार्ग दिखाकर सफलता की ओर ले जाते है हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु बनाकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते रहें। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के सभी मंडलों के प्रमुख धार्मिक स्थानों पर भाजपा नेता व जनप्रतिनिधियों ने पंहुचकर गुरुओं और साधु संतो का सम्मान किया। कार्यक्रम जिला संयोजक भाजपा जिला उपाध्यक्ष विश्वास पांडे, खेल प्रकोष्ठ संयोजक लाखन सिंह नवासा ने खेल प्राधिकरण जेतपुरा में खेल प्रशिक्षकों का सम्मान किया । इसी प्रकार डॉ शरद विजयवर्गीय दिलीप पटोदिया जगदीश जाट पूनमचंद फकीरा दीपक फेमस सहित अनेक भाजपा नेता व पदाधिकारियों ने विभिन्न धार्मिक गुरु स्थानों पर साधु संतों गुरुओं का सम्मान किया।

झाड़-फूंक में जाती है जानें, सर्पदंश से निपटने जिला प्रशासन कर रहा जागरूक

सर्पदंश- पिछले 15 माह में सर्पदंश के 521 लोग शिकार, लगभग 50 की मौत

संजय द्विवेदी, बैतूल। हर साल मानसून में सर्पदंश के मामले बढ़ते हैं। कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि सर्पदंश की घटना के बाद लोग उपचार में लापरवाही या लेटलतीफी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सांप काटने पर झाड़-फूंक का ही सहारा लिया जाता है। अगर जिले की बात करें, तो वर्ष 2024-25 में सर्पदंश के 471 मामले सामने आए थे। वहीं 2025-26 में अब तक करीब 41 मामले आ चुके हैं। चिकित्सकों की मानें, तो लोगों द्वारा सावधानी नहीं बरते जाने के कारण बारिश में सर्पदंश की घटनाएं ज्यादा होती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ ही प्रजापति के सांप है जिसके काटने से मौत होती है। खासकर कोबरा, रसेल वाइपर और करैत प्रजाति के सांपों काटने से लोगों की मौत होती है। अगर सर्पदंश के तुरंत बाद समय पर इलाज के लिए मरीज को अस्पताल ले जाये, तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग झाड़-फूंक कराते है और इसके बाद इलाज में देरी के कारण लोगों की जान तक चली जाती है।

15 माह में 521 मामले, 50 की लगभग मौत: मौसम बदलने के साथ सर्पदंश की घटनाओं के मामले आना शुरू हो गए हैं। हर साल कई लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं। बीते 15 माह में जिले में सर्पदंश के 521 मामले जिला अस्पताल में पहुंचे हैं। इससे हर साल 40 से 50 लोगों की मौत हो रही है।

सर्पदंश से पीड़ित को बचाने के लिए इस वर्ष बारिश के पूर्व ही प्रत्येक विकासखंड में इसकी व्यवस्था करा दी गई है। लगभग 25 से 30 वायल एंटी स्नेक वेनम जिले के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध कराए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एंटी स्नेक वेनम की सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। असमय किसी को भी अपनी जान सपदंश के कारण न गंवाना पड़े।

सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में सर्पदंश की घटनाएं: जिले की अधिकांश आबादी ग्रामीण अंचलों में बसी है। इन इलाकों में जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा अधिक होता है। यही कारण है कि सर्पदंश से मरने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक है। चिकित्सक भी इन मौतों का कारण जागरूकता का अभाव बताते हैं। इसलिए समय पर इलाज जरूरी है, लेकिन ग्रामीण उपचार न कराते हुए पहले झाड़-फूंक में ही लगे रहते हैं। इस दौरान जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और मौत हो जाती है। जानकार बताते है कि कई बार मौत का कारण जहर नहीं, बल्कि घबराहट भी होती है। डर से बीपी बढ़ता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की आशंका होती है। कई मामले ऐसे भी आए, जहां सांप जहरीला नहीं था, लेकिन व्यक्ति की मौत कार्डियक अरेस्ट से हो गई।

जिला प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान : जिले में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं और इससे होने वाली मौतों को रोकने जिला प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है। बताया गया कि सर्पदंश के बाद शांत रहें और घबराएं नहीं, घबराने से हृदय की गति बढ़ जाती है, जिससे जहर का फैलाव शरीर में तेजी से हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति का सिर ऊंचा रखकर लिटाएं। घाव को साफ पानी एवं साबुन से धो लें। घाव से खून का रिसाव होने दें। घाव पर ढीली व साफ पट्टी रखें। पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके, नजदीकी स्वास्थ्य संस्था में ले जाकर उपचार करवाएं। यदि संभव हो तो सांप की पहचान करने की कोशिश करें। सांप को पकडऩे या मारने का प्रयास न करें।

इनका कहना है -

जिला अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त उपलब्ध है, क्योंकि जिले भर के सर्पदंश से पीड़ित सबसे ज्यादा मरीज जिला अस्पताल में ही पहुंचते हैं। इसलिए पर्याप्त स्टॉक रखा जाता है। सामुदायिक केंद्रों पर भी एंटी स्नेक वेनम दिए गए हैं।

- डॉ जगदीश घोरे, सिविल सर्जन जिला अस्पताल बैतूल

नगर पालिका द्वारा पहले एक प्रशिक्षित प्राइवेट व्यक्ति, जो सांप पकड़ने में माहिर था, को अनुबंधित किया गया था, परंतु उसके बीमार पड़ जाने के बाद हमारे द्वारा नागरिकों के घरों में निकलने वाले सांप आदि को पकड़ने हेतु फॉरेस्ट विभाग की सहायता से ही यह कार्य किया जाता है।

- सतीश मटसेनीया, सीएमओ, नगर पालिका बैतूल

मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक आज

बैतूल। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक आज 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे लिंक रोड स्थित कैंपेन हाउस में आयोजित की गई है।एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष बीपी धामोढ़े ने बताया कि हाल ही में जबलपुर स्थित कोकिला रिसॉर्ट में 24 जून को आयोजित प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी इस बैठक में दी जाएगी। बैठक में महंगाई राहत से संबंधित धारा 49(6) तथा पेंशन एस्क्रो गारंटी के संबंध में शासन से की जा रही मांग पर चर्चा होगी। इस संदर्भ में एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. जयसवाल एवं अन्य पदाधिकारी 20 जुलाई को ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट कर विषय की गंभीरता से अवगत कराएंगे। इसके अतिरिक्त पेंशन कम्युटेशन की अवधि को लेकर फैली भ्रांतियों, इंदौर उच्च न्यायालय के निर्णय की वास्तविक स्थिति, 79 वर्ष की आयु में 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि, आठवें वेतन आयोग में पेंशनर्स को संभावित सुविधाएं, लंबित भुगतान, कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना की प्रगति तथा संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर भी विस्तार से विचार किया जाएगा। श्री धामोढ़े ने सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

रोजगार मेले में 68 अभ्यर्थियों का चयन

बैतूल। जिला रोजगार कार्यालय, आईटीआई, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के संयुक्त तत्वाधान में युवा संगम के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेले का आयोजन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में किया गया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में कुल 158 आवेदकों ने पंजीयन कराया था। जिसमें 07 कम्पनियों के द्वारा 68 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन कर 04 को लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए गए। रोजगार मेले के साथ ही आईटीआई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ परिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 92 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें 36 जांच सिकलसेल की गई।

विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

- स्वास्थ्य संस्थानों में चलेगा विशेष प्रचार अभियान, परिवार नियोजन पर रहेगा फोकस

बैतूल। विकास खण्ड चिचोली में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या स्थिरीकरण माह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और जनजागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी चिचोली डॉ राजेश अतुलकर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसके साथ ही 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थिरीकरण माह के रूप में अभियान संचालित किया जाता है। इस वर्ष भी यह अभियान विकास खण्ड चिचोली के सभी स्वास्थ्य संस्थानों और जनसमुदाय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें परिवार नियोजन के महत्व का प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाएगा और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सालय चिचोली में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ राजेश अतुलकर के निर्देशन में डॉ संदीप धुर्वे, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर अनिल उईके, बीपीएम एकनाथ ठाकुर, बीसीएम विनीत आर्य, एमटीएस पंकज डोंगरे सहित कार्यालयीन और मैदानी कर्मचारियों ने सहभागिता की।

वर्षा ऋतु में कोई भी जन-धन की हानि न हो, अधिकारी अलर्ट रहें : संभागायुक्त

संभागायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित

बैतूल। वर्षा ऋतु के दौरान सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ और सम्बन्धी विभागों के अधिकारी सतर्क रहें। सुरक्षा के सभी पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। सार्वजनिक इमारतों, स्कूल भवनों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केन्द्रों पर सतत नजर बनाएं रखें। जर्जर भवनों को तत्काल डिस्मेंटल कराएं। किसी भी प्रकार की जनहानि और धन हानि न हो यह सुनिश्चित किया जाएं। यह निर्देश संभागायुक्त नर्मदापुरम श्री के जी तिवारी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट बैतूल में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, वन मंडल अधिकारी उत्तर नवीन गर्ग, वन मंडल अधिकारी वरुण यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, प्रशिक्षु आईएफएस सुंदर निवेदन, उपायुक्त नर्मदापुरम भी गणेश, अपर कलेक्टर श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव सहित जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि जनसामान्य के कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से किया जाएं। जनपद सीईओ, सीएमओ नगरपालिक , सडक़ विभाग सतत अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते रहे और सुनिश्चित करें कि सडक़ों को स्थित अच्छी रहे। सडक़ों पर गड्ढे होने की शिकायतों का त्वरित निराकरण कराएं। इसी प्रकार नाली के ब्लॉकेज, पेयजल, बिजली, जलभराव की समस्याएं आने कर उनका तत्परता से समाधान कराएं। संभागायुक्त श्री तिवारी ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार हैं। विभागीय अधिकारियों से समन्वय और सहयोग से कार्य करना आपका प्रमुख उत्तरदायित्व हैं। इसी प्रकार विकास से जुड़े कार्यों में भी एसडीएम लीडरशिप लें। अपने क्षेत्र में फीड बैक सिस्टम डेवलप करें। नकारात्मक खबरों पर त्वरित एक्शन लिया जाएं। रोस्टर तय कर विभागों के कार्यों का निरीक्षण किया जाएं। उन्होंने सभी सीएमओ,जनपद सीईओ और बीएमओ से वर्षा की तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कोई भी ऑफलाइन दर्ज न हो राजस्व प्रकरण

वन खंड व्यवस्थापन के प्रकरणों की अनुविभागवार समीक्षा कर संभागायुक्त श्री तिवारी ने कहा कि प्रकरणों में आवश्यक बिंदुओं का पालन कर उन्हें दर्ज कराएं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों से ऑफलाइन दर्ज प्रकरणों के बारे में जानकारी और निर्देशित किया कि कोई भी प्रकरण ऑफलाइन दर्ज नहीं किया जाएं। ऑफलाइन दर्ज पाए जाने पर संबंधित एसडीएम के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम और एसडीओ फॉरेस्ट की जानकारी और समन्वय में कमी न हो। उन्होंने स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अन्य संबंधित विभागों को वन विस्थापन के प्रकरणों का एसडीओ फॉरेस्ट से समन्वय कर निराकरण कराए। सभी राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं।

निजी स्कूल वाहनों की करें जांच

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम सुनिश्चित करे कि ज्ञात और अज्ञात वाहन से होने वाली दुर्घटना में राहत के प्रकरण लंबित न रहें। अपने क्षेत्र के थाने के साथ राहत प्रकरणों की सतत समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा के दृष्टिगत अपने क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन कर वहां सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। निजी बस वाहनों की निरीक्षण भी किया जाएं। निजी स्कूल बस वाहन की फिटनेस, वाहन चालक सहित अन्य आवश्यक प्रमाणित जानकारी ली जाएं। अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही कराएं।प्रदूषण के दृष्टि से पॉल्यूशन कंट्रोल द्वारा औद्योगिक इकाइयों की भी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएं। संभागायुक्त श्री तिवारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गंभीरता से कार्य करें।

इस युग के हम साक्षी हैं यह परम सौभाग्य : योगेश पंडाग्रे

बैतूल। शासकीय कन्या गंज के सभागार में मेरा युवा भारत बैतूल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम आमला विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, समाजसेवी ऋषिराज सिंह परिहार व प्राचार्य ललित लिल्होरे जिला युवा अधिकारी के आतिथ्य में और माय भारत की जिला अधिकारी श्रीमती सुषमा गवली की अध्यक्षता में हुआ।

जिला अधिकारी सुषमा गवली ने बताया कि युवा मंडल महिला मंडल समाज सेवा के सहयोग से यह अभियान निरंतर चला जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक पौधों का रोपण हो सके इस क्षेत्र में हम सभी पहल कर रहे हैं। ऋषिराज सिंह परिहार ने कहा कि हम सभी का एक विशेष दायित्व बनता है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए पौध रोपण करने की आवश्यकता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण प्रदान कर सके इसके लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे ने कहा कि हम भाग्यशाली है जो कि इस युग के साक्षी बन रहे है। भारत सरकार देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान को चला रही है इस अभियान को हम जन-जन तक पहुंचाएं। डॉ.शंकर सातकर ने भी पर्यावरण पर अपने विचार रखे। डॉ.पंडाग्रे ने ग्लोबल वार्मिंग विषय पर स्कूल बच्चो से परिचर्चा की और सभी को सामूहिक तौर पर एक पेड़ मां के नाम की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर डॉ.शंकर सातकर ने बड़े विस्तार पूर्वक प्रकृति पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन धनंजय सिंह ठाकुर ने व अभार प्राचार्य ललित लिल्होरे ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर इस अवसर पर पिकी भाटिया, महेश गुजेले, रामनारायण शुक्ला, राधेलाल बनखेडे, हुकुमचंद कालभोर, शुभम गोचरे, राकेश मन्नायासे, शिवसागर सिंह, जीवन उच्चसरे, मलूकचन्द पवार, हेमन्त विश्वकर्मा, शैलेन्द शर्मा, गजेंद्र पवार, हिमांशु मालवीय शाहिद युवा मंडल महिला मंडल व शारदा समिति के पदाधिकारी सहित सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने किया आवास अनुदान का वितरण, बैतूल के 130 हितग्राही लाभान्वित

चयनित पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रों का किया वितरण

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश के 60 हजार से अधिक हितग्राहियों को एक क्लिक के माध्यम से 1,513.53 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का भी वितरण किया। इसी के अंतर्गत बैतूल जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका के बाल सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, सभापति नितेश परिहार, वरिष्ठ पार्षद रघुनाथ लोखंडे, पार्षद श्रीमती सोमती धुर्वे, अशोक नागले, एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मत्सानिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बैतूल नगर पालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चयनित पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। इसके साथ ही बैतूल में निर्मित बारह आवासों में विधिवत गृह प्रवेश भी संपन्न हुआ।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 130 पात्र हितग्राही है। बाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर से हो रहे मुख्य आयोजन का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं हितग्राहियों ने देखा।

देश में गरीबों के लिए आवास और अन्न का प्रबंध करने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री : पार्षद शर्मा

आमला । देश में आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद गरीबों के आवास और अन्न के लिए पहली बार धरातल पर युद्ध स्तर पर काम होते देखा है, पहले हर गरीब का बस यही सपना होता था कि उसकी भी कभी पक्की छत होगी, और परिवार को पेट भर अन्न मिल पाएगा ।गरीबों का ये सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है, अब हर गरीब के पास अपना पक्का मकान और राशन भी फ्री मिल रहा है, उक्त वक्तव्य वार्ड 5 के पार्षद राकेश शर्मा ने नगर पालिका सभा कक्ष में एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव सिटीज ऑफ़ टुमारो के वर्चुअल कार्यक्रम में कहे । कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के उद्बोधन को भी टीवी पर देखा, सुना गया इस मौके पर नगर पालिका के नवागत मुख्य नगरपालिका अधिकारी नितिन बिंजवे का सभी पार्षदों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और शहर के कार्यों में उनसे तेजी लाने की अपेक्षा भी की है । इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे ने अपने संबोधन में कहा कि आवास योजना के लाभार्थी शीघ्र अपने आवास के काम को गंभीरता पूर्ण करें, साथ ही ऐसे हितग्राही जो अभी तक इस योजना से वंचित रह गए हैं उन्हें भी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेना चाहिए ।

कलेक्टर-एसपी ने बाढ़ राहत की तैयारियों, मूंग उपार्जन केंद्रों, बीएलओ प्रशिक्षण एवं धरती आबा शिविर का किया निरीक्षण

बाढ़ राहत एवं बचाव की तैयारियों को रखा जाए चाक चौबंद : कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला ने भैरूंदा में चल रहे बीएलओ प्रशिक्षण, लाड़कुई और रेहटी में बनाए गए मूंग उपार्जन केंद्र एवं ग्राम कोसमी में लगाए गए धरती आभा अभियान के शिविर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंनें बाढ़ राहत एवं बचाव की तैयारियों के संबंध में ग्राम छिंदगांव काछी पहुंचकर कोलार नदी, नीलकंठ एवं आंवलीघाट पहुंचकर नर्मदा नदी तथा रेहटी थाने का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भैरूंदा एसडीएम श्री मदनसिंह रघुवंशी, बुधनी श्री डीएस तोमर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बाढ़ राहत एवं बचाव की तैयारियों का किया निरीक्षण

कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा एसपी श्री शुक्ला ने ग्राम छिंदगांव में कोलार नदी तथा नीलकंठ एवं आंवलीघाट पर बाढ़ राहत एवं बचाव के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्मदा तथा कोलार नदी का जल स्तर भी देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि नदियों में बाढ़ के दौरान बाढ़ आपदा एवं अन्य स्थितियों से निपटने के लिए सभी तैयारियां चाक चौबंद रखी जाएं। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव के सभी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चिन्हित शिविर स्थलों के अतिरिक्त कंट्रोल रूम को भी सक्रिय रखें, ताकि सूचना मिलते ही त्वरित राहत एवं बचाव की कार्रवाई कर जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पुल, पुलिया एवं रपटों सहित पहुंच मार्ग की निगरानी की जाए और पुल पुलियों पर पानी होने की स्थिती में नागरिकों को इन्हें पार करने से रोका जाए। इसके लिए भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने बाढ़ राहत एवं बचाव की तैयारियों के संबंध में रेहटी थाने का भी निरीक्षण किया।

मूंग उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण : कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा एसपी श्री शुक्ला ने लाड़कुई एवं रेहटी में मूंग उपार्जन के लिए बनाए गए उपार्जन केंद्रो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रो पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि विक्रय के लिए उपज लेकर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। यदि किसानों को कोई समस्या आये तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल, बैठने के लिए कुर्सियों सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में तौल कांटे, हम्माल एवं तुलावटी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।

ग्राम कोसमी पहुंचकर धरती आबा शिविर का किया निरीक्षण

कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा एसपी श्री शुक्ला ने ग्राम कोसमी में धरती आबा अभियान के तहत आयोजित किए गए शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं से लाभान्वित किया जाए, कोई भी पात्र हितग्राही न छूटे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि किस परिवार को कौन सी योजना का लाभ अभी तक नही मिला है और उस योजना से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। यह अभियान जनजातीय आबादी के लिए समान अवसरों का सृजन, सामाजिक-आर्थिक स्तर का विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति के उद्देश्य चलाया जा रहा है जो सरकार का प्राथमिकता वाला अभियान है। सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी शिविरों में समय पर उपस्थित हो और जनजातीय समुदाय के सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करें।

बीएलओ प्रशिक्षण का किया निरीक्षण

कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा एसपी श्री शुक्ला ने भैरूंदा में बूथ लेवल ऑफिसर्स को दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले मास्टर ट्रेनर्स को निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ की सभी शंकाओं का समाधान किया जाए।

उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची के सुधार एवं बूथ लेवर ऑफिसर्स की शंकाओं का समाधान करना हैं। प्रशिक्षण के दौरान सभी बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, संशोधन करना सहित अन्य बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानकरी दी जाए। इसके साथ ही सभी को बीएलओ के दायित्वों के बारे में भी बताया जाए, ताकि मतदाता सूचि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

संक्षिप्त समाचार

निर्वाचक नामावली त्रुटिरहित बनाने बीएलओ को दिया जा रहा है प्रशिक्षण

रायसेन (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के त्रुटिरहित बनाने के निर्देशों के अंतर्गत बीएलओ क्षमता विकास हेतु जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 07 जुलाई से 17 जुलाई 2025 तक बीएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस 08 जुलाई को जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141-भोजपुर में 86 बीएलओ, 142-सॉची में 114 बीएलओ तथा 143-सिलवानी में 67 बीएलओ को विधानसभावार पृथक-पृथक कक्षों में जिला एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें विविध प्रावधानों एवं निर्वाचक नामावली प्रक्रिया, फॉर्मो को भरना तथा केस स्टडीज, बीएलओ एप आदि का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आयोग के निर्देशानुसार प्रशिक्षित बीएलओ का ऑनलाईन मूल्यांकन किया गया।

प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप मिलने से खुश हैं सुमित सिंह

रायसेन (निप्र)। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। रायसेन निवासी सुमित सिंह ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय रायसेन में कक्षा 12वीं की परीक्षा 88.6 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण की है और उन्हें प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रू की राशि प्राप्त हुई है। लैपटॉप खरीदने हेतु राशि मिलने से सुमित सिंह बेहद खुश हैं और प्रतिभाशीली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहते हैं उन्हें लैपटॉप मिलने से ऑनलाइन अध्ययन, डिजिटल संसाधनों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। यह लैपटॉप उनकी पढ़ाई को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाएगा। सुमित ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने और डिजिटल शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए की जा रही यह पहल छात्रों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीएलओ क्षमता विकास हेतु जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ को दिया जा रहा है प्रशिक्षण

रायसेन (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के त्रुटिरहित बनाने के निर्देशों के अंतर्गत बीएलओ क्षमता विकास हेतु जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 07 जुलाई से 17 जुलाई 2025 तक बीएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण के तृतीय दिवस 09 जुलाई को जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्रमांक 140-उदयपुरा में 91 बीएलओ, 141-भोजपुर में 87 बीएलओ, 142-सॉची में 50 बीएलओ तथा 143-सिलवानी में 67 बीएलओ को विधानसभावार पृथक-पृथक कक्षों में जिला एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें विविध प्रावधानों एवं निर्वाचक नामावली प्रक्रिया, फॉर्मो को भरना तथा केस स्टडीज, बीएलओ एप आदि का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आयोग के निर्देशानुसार प्रशिक्षित बीएलओ का ऑनलाईन मूल्यांकन किया गया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 142-सॉची अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायसेन (डाईट) में आयोजित बीएलओ प्रशिक्षण का उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने सभी बीएलओ को पूरी गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करने सहित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मदिरा के अवैध विक्रय के विरुद्ध कुल 8 प्रकरण दर्ज

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन में आबकारी विभाग के दल ने मंगलवार को मदिरा के अवैध विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण व परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही की। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी विभाग के दल ने हरदा के खेड़ीपुरा मोहल्ला, ग्राम कमताड़ा, मसनगांव, धूपकरण, रहटाकलां, बिचपुरी सर्कुलर व सांवलखेड़ा में दबिश दी। दबिश के दौरान 29 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब एवं 410 किलो महुआ लाहन जप्त कर कुल 8 प्रकरण दर्ज किये। जप्त मुद्देमाल का अनुमानित बाजार मूल्य 46800 रुपये है।

नशे के सौदागरों पर करें कड़ी कार्रवाई, नशीली सामग्री के तंत्र को करें समाप्त : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

नशे से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास की भी करें व्यवस्था

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा संभाग में पिछले 6 महीने में नशामुक्त अभियान में अच्छा कार्य किया गया है। बड़ी संख्या में नशे के व्यापार संलिप्त व्यक्तियों को जेल भेजने के साथ गांजा और कोरेक्स की भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। नशा व्यक्ति के तन, मन और धन तीनों का विनाश करता है। रीवा और पूरे विन्ध्य क्षेत्र में चारों ओर हो रहा तेजी से विकास तभी सार्थक होगा जब भावी पीढ़ी को नशे से दूर रखा जाए। भावी पीढ़ी नशे की राह पर चली गई तो हर तरह का विकास बेमानी हो जाएगा। सर्किट हाउस रीवा में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नशामुक्त भारत अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि कोरेक्स तथा अन्य नशीले कफ सिरप जहाँ पर बनाए जाते हैं वहाँ से जिले में पहुंचने और बिक्री होने तक के पूरे तंत्र पर कड़ी निगरानी रखकर कार्रवाई करें। नशे के सौदागरों को जेल में भेजने के साथ कड़ी सजा दिलाने के प्रयास करें। अपराधियों पर कार्रवाई के साथ-साथ नशीले पदार्थों के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास के भी प्रयास करें। इस कार्य में विभिन्न विभागों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आमजनों का पूरा सहयोग प्राप्त करें। नशा सामाजिक और आर्थिक बुराई होने के साथ-साथ अपराधों का भी मूल है। पूरे संभाग में नशे के विरूद्ध बड़ा जागरूकता अभियान चलाएं। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने संभाग विशेषकर रीवा जिले में नशे के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने में दो करोड़ से अधिक राशि के नशीले कप सिरप और गांजा की जप्ती की गई है। संभाग में अभियान चलाकर एक दिन में ही अवैध शराब के निर्माण पर कार्रवाई करते हुए 1017 आरोपियों को गिरफ्तार कर 22 लाख रुपए की अवैध शराब जप्त की गई। नशे के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रीवा जिले में वर्ष 2023 में 176, वर्ष 2024 में 162 तथा वर्ष 2025 में अब तक 129 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आमजनता से संवाद के लिए थाना स्तर पर जनचौपाल का आयोजन करके आमजनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। पुलिस ने पशु तस्करों पर कार्रवाई करते हुए दो हजार से अधिक पशुओं को मुक्त कराकर विभिन्न गौशालाओं में भेजा है। पशु तस्करी में लिप्त 32 आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस ने 250 से अधिक गुमे हुए व्यक्तियों को बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा है। पुलिस महानिरीक्षक ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही रात्रिकालीन गश्त, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी तथा अन्य कार्यवाहियों की भी जानकारी दी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जीतू पटवारी ने 14 दिन से लापता गजराज लोधी परिवार की गुमशुदगी को लेकर उठाए गंभीर सवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अशोकनगर जिले के मूडरा/मुंगावली क्षेत्र में गजराज लोधी, उनके भाई रघुराज लोधी और पूरे परिवार की रहस्यमय गुमशुदगी को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। श्री पटवारी ने यह भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह स्वयं गांव में जाकर परिजनों से मिले थे। परिवारजनों ने बताया कि– एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही गजराज और रघुराज लोधी अपने पूरे परिवार के साथ लापता हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि यह मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार का नहीं रहा, बल्कि यह मध्यप्रदेश की भयावह कानून व्यवस्था, माफिया तंत्र और सरकार की तानाशाही मानसिकता को उजागर करता है। 14 दिन बीत चुके हैं, पूरा परिवार लापता है – क्या सरकार जानबूझकर सच्चाई दबा रही है?

एम्स भोपाल ने मनाया विश्व जनसंख्या दिवस 2025, युवाओं को सशक्त बनाकर

परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता पर दिया जोर

भोपाल। एम्स भोपाल ने अपने कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हुए जनसंख्या वृद्धि से जुड़े मुद्दों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। इस अवसर पर संस्थान ने परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस वर्ष की थीम युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना युवाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और निर्णय लेने के अधिकार को केंद्र में रखती है। एम्स भोपाल ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे संतुलित जनसंख्या को एक स्वस्थ, समावेशी और टिकाऊ समाज की नींव मानें और परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करने में सहयोग करें। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा- युवाओं को जानकारी, पहुंच और विकल्पों से सशक्त करना ही सतत विकास की कुंजी है। जनसंख्या संतुलन केवल आँकड़ों का विषय नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता सुधारने, भविष्य को सुरक्षित करने और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करने का मार्ग है। एम्स भोपाल इसके लिए जन-जागरूकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। एम्स भोपाल द्वारा इस अवसर पर डिजिटल माध्यम से जागरूकता संदेश जारी किए गए तथा सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा इकाइयों के माध्यम से जनजागरूकता को प्रोत्साहित किया गया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने जिला अस्पताल रीवा में नवनिर्मित ओपीडी भवन का किया निरीक्षण

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा में नवनिर्मित नवीन ओपीडी भवन का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री श्री ने कहा कि नवीन भवन के संचालन की सभी तैयारियाँ कर लें। इसमें आवश्यक उपकरण तथा फर्नीचर लगा दें। इसके विभिन्न कक्षों को निर्धारित विभागों को कार्य करने के लिए आवंटित कर दें। नवीन ओपीडी भवन से जिला अस्पताल में आने वाले रोगियों को उपचार की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार जिला चिकित्सालय में नवीन भवन के साथ 300 बिस्तर में भर्ती की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह ने नवीन भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी दी। स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, सिविल सर्जन डॉ प्रतिभा मिश्रा, अन्य चिकित्सा अधिकारी, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के पक्के आवास के सपने को पूरा कर रही है : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को किया हितलाभ वितरण

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के पक्के आवास के सपने को पूरा कर रही है। योजना से देश में 4 करोड़ पक्के आवास लोगों को मिल चुके हैं आने वाले समय में 3 करोड़ मकान गरीबों को दिये जायेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नगर निगम रीवा के टाउन हाल में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 224 हितग्राहियों को आवास की एक लाख रूपये की प्रथम किश्त के स्वीकृति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश के 65 हजार से अधिक हितग्राहियों को 1626 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से हितग्राहियों को राशि का वितरण किया। कार्यक्रम का संजीव प्रसारण कार्यक्रम में दिखाया गया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से रीवा में 1736 आवास तैयार किये जा चुके हैं। इसी प्रकार पूर्व में 4198 आवास पूर्ण हो गये हैं तथा 224 हितग्राहियों को प्रथम किश्त के तौर पर एक लाख रूपये की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का संकल्प है कि कोई भी गरीब कच्चे आवास में न रहे। उनकी संकल्पना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रदेश व जिले में भी गरीबों को पक्के आवास प्रदान किये जा रहे हैं।

सीएमएचओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसदेही का किया निरीक्षण

कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने की दी चेतावनी

बैतूल (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े ने 9 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसदेही का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता रखने, मरीजों को बैठने की आवश्यक व्यवस्था करने, समस्त काउंटर चिकित्सालय समय पर विधिवत खोलने एवं समय पर उपचार करने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ स्वाति बरखड़े को भी आवश्यक निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉ.हुरमाड़े ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप भैंसदेही चिकित्सालय में प्रसूता श्रीमती सोनाली पत्नी श्री सदाशिव बड़ोदे एवं श्रीमती पूनम पत्नी श्री राजेश पांसे निवासी बालनेर को उनके नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ही प्रदान किए। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल प्रशासन की तत्परता को दर्शाती है, बल्कि नवजात के अधिकारों की शुरुआत को भी मजबूत करती है। डॉ.हुरमाड़े ने बताया कि छुट्टी के समय ही सभी प्रसूताओं को जन्म प्रमाण-पत्र वितरित किया जाना प्रारंभ करने से प्रमाण-पत्र वितरण में आने वाले अनावश्यक विलम्ब एवं प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिए आने-जाने की असुविधा से राहत मिलेगी।

जन्म प्रमाण-पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके आधार पर शिशु के आगामी पहचान पत्र बनाए जाते हैं। सीएमएचओ डॉ हुरमाड़े द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसदेही के समस्त मैदानी अमले सीएचओ, सुपरवाईजर, एएनएम की समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा ली गई। सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग एवं टीबी स्क्रीनिंग को तत्काल रूप से बढ़ाने के निर्देश दिए। विकासखंड के टीबी एवं सिकल सेल स्क्रीनिंग की लक्ष्य पूर्ति में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने एवं किस प्रकार शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा सकती है तथा इसकी मॉनिटरिंग के विषय में विस्तृत निर्देश दिए। उन्होनें मातृ-मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उपाय बताये हुए इसे कम करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जनसंख्या स्थिरीकरण माह के बारे में आवश्यक जानकारी देकर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त भारत अभियान तथा एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भी समीक्षा की।

उन्होंने समस्त सीएचओ, सुपरवाईजर, एएनएम को सख्त दिए कि अपने निर्धारित मुख्यालय पर निवास करें अन्यथा आगामी माह में उनका वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रातः 9 बजे तक अनिवार्य रूप से खोले जाए, समस्त सुपरवाईजर, एएनएम प्रतिमाह की 5 तारीख तक अपना टूर प्रोग्राम अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करें। साथ ही उन्हें दैनिक डायरी लिखने के भी निर्देश दिए गए। समस्त सीएचओ, एएनएम, आशा सुपरवाईजर एवं सहयोगी अपने निर्धारित यूनीफार्म में रहने के लिए निर्देशित किया।

पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए कार्य कर रही है राज्य सरकार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विकसित भारत @2047 के लक्ष्य तक पहुंचने में देश के युवाओं की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

- विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई करें, उनके उज्जवल भविष्य की चिंता सरकार करेगी
- इंदौर में पुण्योदय प्रकल्प द्वारा विद्यार्थियों को किया गया कॉपी वितरण
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम को किया संबोधित

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2047 तक भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा और इसमें देश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रदेश सरकार बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है। सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं।

शासकीय स्कूलों में कक्षा 6 और 9 के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख साइकिलें वितरित की जा रही हैं। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करवाकर दी जाएंगी। सरकार ने शैक्षणिक-सत्र की शुरुआत से पहले ही बच्चों को किताबें बांटी हैं। अब पुण्योदय प्रकल्प के माध्यम से कॉपियां भी उपलब्ध करा रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को इंदौर में हिंद रक्षक संगठन द्वारा पुण्योदय प्रकल्प के 21वें वर्ष के अवसर पर बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स परिसर में प्रियजनों की पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्वलित कर कॉपी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क कॉपी वितरित की।

स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में बच्चों के सपने पूरे किए जा रहे हैं, जो विद्यार्थी स्कूल में टॉप करेगा, राज्य सरकार उसे इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान करेगी। नीट पास करने वाले विद्यार्थियों के चिकित्सा शिक्षा की फीस में भी सरकार सहायता कर रही है। आगामी दो वर्ष में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 50 तक पहुंचेगी। सरकार द्वारा युवाओं के स्वावलंबन के लिए प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर पूर्व मंत्री स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवनकाल में समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत से उल्लेखनीय कार्य किये। विद्यार्थियों को नि:शुल्क कॉपियां वितरण का कार्य भी उनकी पुण्य-स्मृति में ही है। इंदौर में प्रतिवर्ष रंगपंचमी मनाने का अपना अलग आनंद है, रंगपंचमी को यह भव्य स्वरूप प्रदान करने का श्रेय भी पूर्व मंत्री स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ को ही जाता है। कार्यक्रम के आयोजक हिंद रक्षक संगठन के संयोजक श्री एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ ने पुण्योदय प्रकल्प के बारे में बताते हुए कहा कि वर्ष 2003 से इंदौर शहर के लगभग 300 समाजसेवी परिवार मिलकर प्रति वर्ष साढ़े तीन लाख से अधिक कॉपियां विद्यार्थियों को प्रति कॉपी मात्र एक रुपए के सांकेतिक शुल्क पर वितरित करते हैं। विद्यार्थियों को कॉपी वितरण का कार्य प्रतिवर्ष 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहता है। उन्होंने इस कार्य में भागीदारी करने वाले सभी परिवारों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक सुश्री ऊषा ठाकुर, महापौर इंदौर डॉ. पुष्यमित्र भार्गव, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं।

कावड़ यात्रियों का पुष्प-वर्षा कर किया स्वागत

कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के साथ होगी माकूल व्यवस्थाएँ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ अनुकूल व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को उज्जैन त्रिवेणी शनिमंदिर से कावड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कावड़ यात्रियों का पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कावड़ का पूजन कर कावड़ उठाई और अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर संत श्री उत्तम स्वामी के साथ पैदल चलकर कावड़ यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी त्यौहार उत्साह के साथ मनाने की परम्परा राज्य सरकार ने शुरू की है। ईश्वर और संतजन के आशीर्वाद से उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियाँ तेजी से की जा रही है। हम इस सोच के साथ सभी तैयारियां कर रहे है कि वर्ष-2028 के बाद यदि प्रतिवर्ष सिंहस्थ जैसे आयोजन हों तो किसी प्रकार की समस्या न आये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत उज्जैन में संतों के लिये आश्रम और अन्य व्यवस्थाओं को जुटाने के लिये सिंहस्थ धार्मिक सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में उज्जैन आने वाले श्रृद्धालुओं के लिये सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित होंगी।

- मुख्यमंत्री उज्जैन में समर्पण कावड़ यात्रा में हुए शामिल

मुख्यमंत्री ने बताया जल का महत्व

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कावड़ यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में कई संस्कृतियाँ हैं, दुनिया में तो 194 देश है लेकिन कोई देश अपने कोई भी शुभ काम प्रारंभ करने के लिए जल के माध्यम से कोई संकल्प नहीं लेता है। भारतीय संस्कृति जल ही जीवन की संस्कृति और जीवन जीने की पद्धति रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ईश्वर की कृपा से हम हजारों सालों से जल के गुणों से परिचित हैं। कावड़ यात्रा मे विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, श्री सतीश मालवीय, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, श्री संजय अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, श्री तपन भौमिक और संतों सहित बड़ी संख्या में श्रृद्धालु उपस्थित थे।

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में डूबा युवक, रेस्क्यू जारी

- खजुराहो में फोरलेन हाइवे पर भरा पानी
- ग्वालियर और रीवा में 9 घंटे में ढाई इंच बारिश
- 20 जिलों में अति भारी बारिश का है अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को कटनी, उमरिया, सीधी और छतरपुर समेत कई जिलों में पानी गिरा। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सतना के चित्रकूट में एक युवक मंदाकिनी नदी में बह गया। उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खजुराहो में लगातार तेज बारिश के चलते झांसी-खजुराहो फोरलेन हाइवे पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। उमरिया जिले में भी झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 20 जिलों में अति भारी बारिश और 12 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बीते 24 घंटे के दौरान रीवा में सबसे ज्यादा 3.7 इंच पानी गिर गया। ग्वालियर में भी भारी बारिश दर्ज की गई। यहां ढाई इंच पानी गिरा। छतरपुर के खजुराहो में 1.9 इंच, जबलपुर में 1.6 इंच, मंडला में 1.4 इंच, टीकमगढ़ में 1.2 इंच और सतना में 1 इंच बारिश हुई।

दतिया, उमरिया, दमोह, बालाघाट, रतलाम, सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, गुना, मऊगंज, सीहोर समेत कई जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहा।

मंडला में अब तक बाढ़ के कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लापता हैं। 300 मकान समेत कई सड़कें और पुलियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 312 लोगों को रेस्क्यू कर 7 राहत कैंप में रखा गया है।

शिवपुरी और ग्वालियर की सीमा पर बना हरसी बांध लबालब भर गया। इससे पानी का ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। इससे दोनों जिलों के करीब 20 गांव में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है।

मैहर में तेज बारिश से मकान की दीवार गिर गई। एक महिला घायल हो गई। उसे सिविल अस्पताल अमरपाटन में भर्ती कराया गया है। सतना में कार पर पेड़ आ गिरा। कार सवार सभी 5 लोग बाल-बाल बच गए लेकिन गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। करीब आधा घंटे तक ट्रैफिक भी अस्त-व्यस्त रहा।

सीधी में 10 घंटे से हो रही बारिश की वजह से मकानों-दुकानों में पानी भर गया है। कहीं-कहीं बिजली भी गुल थी।

गुना में लल्लू बैरागी (6) और कबीर मीना (8) नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। रात करीब साढ़े 9 बजे मछली पकड़ने वाले जाल की मदद से शव नदी से बाहर निकाले गए।

आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे की मौत

शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 13 साल के लड़के की मौत हो गई। टांघर गांव का रहने वाला मनीष सिंह गोड़ खेत में काम कर रहा था। तभी हादसे का शिकार हो गया।

कटनी में सुबह से बारिश, सड़कें जलमग्न

कटनी में शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। लखेरा से एसीसी फैक्ट्री तक जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया है। साउथ रेलवे स्टेशन की अंडर ब्रिज में भी पानी भर गया है। अंडरब्रिज का पानी बस्तियों के घरों में घुस गया है। इधर, रंगनाथ नगर से साउथ रेलवे जाने का रास्ता भी बंद हो गया है।

खजुराहो में फोरलेन पर भरा 3 फीट तक पानी

खजुराहो में झांसी-खजुराहो फोरलेन पर बमीठा से खजुराहो के बीच पर करीब 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। इससे आवागमन बाधित हो गया है।

उमरिया में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी: उमरिया में जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले में शुक्रवार सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। उमरिया में शहर की सड़कों पर पानी भर गया है।

खजुराहो में अस्थाई पुल बहा, तीन गांवों का संपर्क टूटा: खजुराहो और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से भूसोर-गंगऊ बांध के बीच पुखराव नाले पर बना अस्थाई पुल तेज बहाव में बह गया है। इसे केन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान पुराने रपटे को तोड़कर बनाया गया था। आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित खरयानी, पलकोहा और ढोड़न गांवों का बाहरी क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है। पलकोहा गांव की गर्भवती महिला प्रसव के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है।

पिछले 24 घंटे में इतनी वर्षा

बांधवगढ़ में 11.8 मिमी
मानपुर में 28.2 मिमी
पाली में 18.6 मिमी
नौरोजाबाद में 25.2 मिमी
चंदिया 21.8 मिमी
करकेली 14.8 मिमी
बिलासपुर में 42.2 मिमी

अचानक बिना काफिले के फल लेने न्यू मार्केट पहुंचे सीएम

- आमजन से मिले ; सिग्नल पर रेड लाइट देखकर रोकी गाड़ी

भोपाल (नप्र)। सीएम डॉ. मोहन यादव गुरुवार रात अचानक न्यू मार्केट में फल खरीदने पहुंच गए। उन्होंने बाजार में आम जनता से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने ठेले वालों से बातचीत की और उनके व्यवसाय के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने एक ठेले वाले से फल खरीदे और भुगतान डिजिटल माध्यम से किया।

बाजार में सीएम को देख चौंके लोग

सीएम को अचानक बाजार में देख लोगों को उनकी सादगी पसंद आई। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके मुख्यमंत्री इतनी सहजता से उनके बीच खड़े हैं। अचानक सीएम को अपने बीच में देखकर लोग अचंभित नजर आए।

काफिले में नहीं, सिर्फ दो गाड़ियों से पहुंचे न्यू मार्केट: मुख्यमंत्री डॉ. यादव सादगी के साथ सिर्फ दो वाहनों में बाजार पहुंचे और 15 मिनट रुक कर फल खरीदे और निवास लौट गए।

ट्रैफिक सिग्नल का किया पालन

आमतौर पर सीएम का काफिला जिस रूट से गुजरता है। अमूमन 10-15 मिनट पहले पुलिस उस रूट पर ट्रैफिक रोक देती है लेकिन, सीएम ने अपने दौरे की किसी को जानकारी नहीं दी। वे जब फल लेकर वापस सीएम हाउस की तरफ जाने लगे तो सिग्नल पर रेड लाइट देखकर उनकी गाड़ी रुक गई। सीएम ने सिग्नल पर ट्रैफिक नहीं रोकने दिया। बल्कि, ग्रीन सिग्नल होने पर ही वे आगे बढ़े। इस दौरान लोगों ने सीएम का यह अंदाज देख वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया।

फर्स्ट फेज का स्कूल चलें अभियान फेल

- अब 16 जुलाई से सेकेंड फेज चलेगा, चाइल्ड ट्रैकिंग एप से डोर टू डोर सर्वे होगा

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में पहले दौर में स्कूल चले हम अभियान सफल नहीं रहा है, इसलिए अब राज्य शासन ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक दोबारा स्कूल चले अभियान शुरू करने का फैसला किया है। दोबारा यह अभियान इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के रिकार्ड में यह बात आई है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन कम हुए हैं। इसलिए अब चाइल्ड ट्रेकिंग एप के माध्यम से डोर टू डोर अभियान चलाकर 6 से 18 साल तक के बच्चों की तलाश की जाएगी। हालांकि विभाग के अफसर अभी इसके रिकार्ड जारी करने से यह कहकर बच रहे हैं कि तीस सितम्बर को इसकी स्थिति सामने आएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने सभी कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा है कि कक्षा 1 से 12 तक एडमिशन 25 मार्च 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। अब शिक्षा पोर्टल 3.0 की समीक्षा से पता चला है कि अभी भी विद्यालयों में सत्र 2025-26 के टारगेट के अनुसार बच्चों का एडमिशन नहीं हो सका है।

मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य में पहली बार दिखा स्याहगोश

कैमरे में कैद हुआ विलुप्तप्राय वन्यजीव, डीएफओ बोले- 15 साल के करिअर में पहली बार देखा

मंदसौर (नप्र)। मंदसौर जिले के गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में एक दुर्लभ वन्यजीव कैराकल यानी स्याहगोश देखा गया है। यह प्रजाति भारत में विलुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है और लंबे समय बाद राज्य के किसी संरक्षित क्षेत्र में दिखा है। यह एक दुर्लभ जंगली बिल्ली की प्रजाति है। दरअसल, 1 जुलाई को वनमंडल मंदसौर के अंतर्गत गांधीसागर अभयारण्य में लगाए गए कैमरा ट्रैप में स्याहगोश को रिकॉर्ड किया गया। कैमरे में एक वयस्क नर स्याहगोश नजर आया। वन अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। जिसके बाद मध्यप्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया साइट '&' पर इसकी जानकारी दी।

डीएफओ बोले- 15 साल के करिअर में पहले कभी नहीं देखा

डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर संजय रायखेरे ने बताया कि गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में कैराकल की मौजूदगी पहली बार दर्ज की गई है। मैंने अपने 15 साल के करिअर में कैराकल को आज तक नहीं देखा था। राज्य में सालों बाद किसी संरक्षित क्षेत्र में इस प्रजाति की पुष्टि हुई है। वन विभाग के मुताबिक यह संकेत है कि गांधीसागर जैसे संरक्षित क्षेत्र अब भी दुर्लभ प्रजातियों के लिए उपयुक्त आवास बने हुए हैं।

रात में सक्रिय और तेज दौड़ने वाला शिकारी

स्याहगोश एक शर्मीला और रात में सक्रिय रहने वाला जानवर है। यह आमतौर पर शुष्क, झाड़ीदार, पथरीले और खुली घास वाले इलाकों में रहना पसंद करता है। इसकी चाल तेज होती है और यह छोटे जानवरों का शिकार करता है।

वन अधिकारियों का मानना- यह खोज संरक्षण प्रयासों की सफलता

वन अधिकारियों का कहना है कि अभयारण्य का पारिस्थितिक तंत्र स्याहगोश जैसी विलुप्तप्राय प्रजातियों को भी आश्रय देने में सक्षम है। यह खोज वन्यजीव शोध और संरक्षण की दिशा में बड़ा संकेत मानी जा रही है। वन विभाग का कहना है कि यह पुष्टि बताती है कि गांधीसागर अभयारण्य जैव विविधता के लिहाज़ से समृद्ध बना हुआ है और वहां की पारिस्थितिकी संतुलित है।

मंडला के एनएच-43 पर कार और ट्राला की टक्कर

व्यवसायी की पत्नी की मौत, पति-बेटा घायल ; ट्राला ड्राइवर रायपुर रोड से गिरफ्तार

मंडला (नप्र)। मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर जबलपुर की ओर जा रही टोयटा कार को सामने से आ रहे ट्राला ने टक्कर मार दी। हादसे में 1 महिला की मौत हो गई, वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार दोपहर 2 बजे की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के तिंदनी में टाटा मोटर्स शोरूम के पास हुई इस टक्कर में कार पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में प्रतिष्ठित व्यापारी, राजुल होंडा के संचालक राकेश चिंटू अग्रवाल अपने परिवार के साथ सवार थे।

व्यापारी की पत्नी की हुई मौत

हादसे में राकेश चिंटू अग्रवाल की पत्नी ऋतु अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वे और उनका बेटा राहुल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत कटरा अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उनका इलाज चल रहा है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे रायपुर रोड से पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।